RNI Regi. CHHHIN/2010/34686 दुर्ग, जून 2024 |वर्ष-17 |अंक-195 |पृष्ठ-40+4 |मूल्य-10 रुपये

लोक शिक्षण लोक जागरण की वैचारिक सम-सामयिकी मासिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आस-पास

(छत्तीसगढ़-मध्यप्रदेश)

डाक पंजीकृत संख्या : छ.ग./दुर्ग संभाग/72/2022-2024 ISSN : 1948-2279-0993

2024 के नतीजे

भाजपा	कांग्रेस
10	01

तीसरी बार स्कोर 10-01

छत्तीसगढ़ से सांसद चुने गए 11 में से 3 लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। इनमें दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडेय और कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत शामिल हैं। बाकी पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इनमें सरगुजा से चिंतामणी महराज, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमंदु से रुपकुमारी चौधरी, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, कांकेर से भोजराज नाग पहले विधायक रह चुके हैं।

Follow us in :
Call on: 9424116987
E-MAIL: pradeepcaap@gmail.com
LOG ON: www.chhattisgarhaaspaas.com

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

21 जून 2024

हार्दिक शुभकामनाएं

योग
तन और मन रहे निरोग

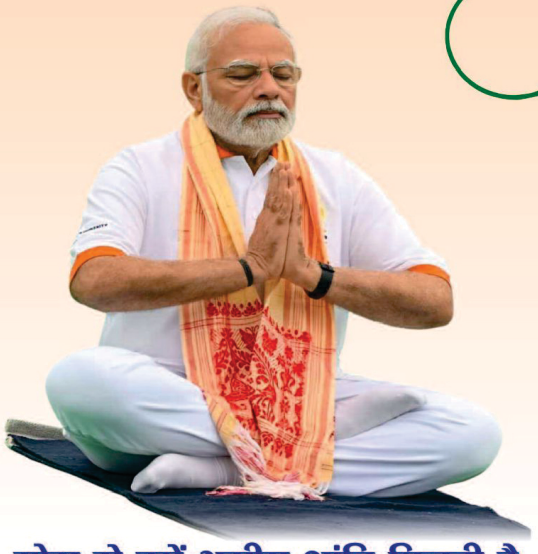

योग से हमें असीम शांति मिलती है, हम जीवन की चुनौतियों का सामना शांति और धैर्य के साथ कर सकते हैं।

- श्री नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ने के लिए यह क्यूआर कोड स्कैन करें ...

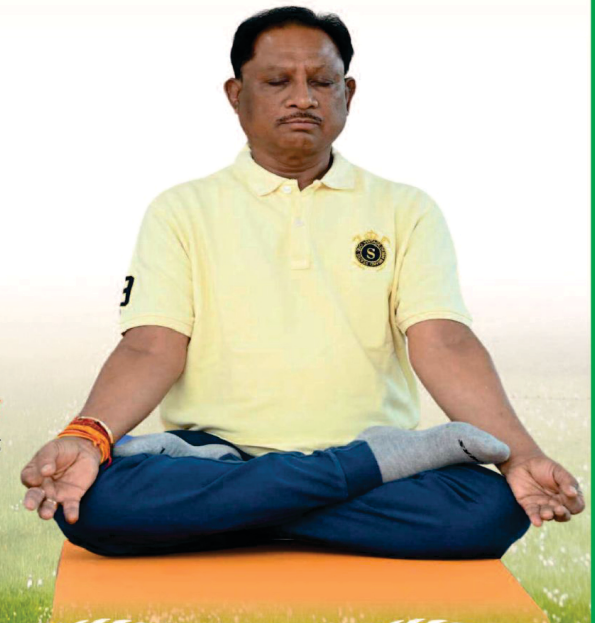

श्री विष्णु देव साय
मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

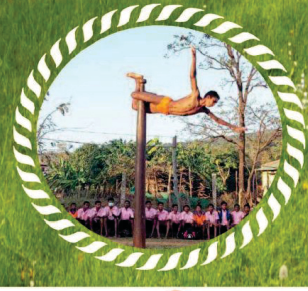

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in

छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

ISSN : 1948-2279-0993

Regi.No.-CHHHIN/2010/34686

हिन्दी मासिक पत्रिका

छत्तीसगढ़ आसपास

■ वर्ष : 17 ■ अंक : 195 ■ जून 2024

मुद्रक-प्रकाशक-प्रधान संपादक
श्रीमति शेफाली भट्टाचार्य

संपादक
प्रदीप भट्टाचार्य

सलाहकार
आलोक कुमार चंदा

पॉलिटिकल एडिटर
संजय कुमार मिश्र

संपादक मंडल

श्रीमती संतोष झांझी
डॉ. नलिनी श्रीवास्तव
डॉ. सोनाली चक्रवर्ती
डॉ. अंजना श्रीवास्तव
डॉ. बलदाऊ राम साहू
संध्या श्रीवास्तव
गोविंद पाल
पल्लव चटर्जी
प्रकाश चंद्र मण्डल
पी. भानुजी राव
अरुण पंडा
परसराम साहू गुरुजी
ठाकुर दशरथ सिंह भुवाल
रामबरन कोरी 'कशिश'
राकेश शर्मा
महेन्द्र मिश्रा
राजन कुमार सोनी

ब्यूरो प्रमुख

डॉ. नौशाद सिद्दीकी
सुरेश वाहने
शमशीर सिवानी

कार्यालय
शेफाली मीडिया पब्लिकेशन ग्रुप

■ 6/बी/6/सेक्टर-6, भिलाई नगर
■ 6/डी/10/सेक्टर-5, भिलाई नगर
जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन-490006
दूरभाष : 09424116987, 0788-2227374
Email : pradeepcaap@gmail.com

मुद्रण

सत्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती शेफाली भट्टाचार्य द्वारा राजहंस प्रिंटर्स, 184, न्यू सिविक सेंटर, भिलाई (छ.ग.) से मुद्रित तथा क्वा. नं. 6/बी, सड़क नं.-6, सेक्टर-6, भिलाई नगर, जिला-दुर्ग (छ.ग.) से प्रकाशित।

संपादक : प्रदीप भट्टाचार्य (संपादकीय टीम पूर्णतः अवैतनिक है।)

संबंद्ध

Chhattisgarh Press Council

छत्तीसगढ़ प्रेस कांउसिल छत्तीसगढ़
पंजीयन क्रं. : 2984

भीतर

www.chhattisgarhaaspaas.com
RNI NO. CHHHIN/2010/34686
छत्तीसगढ़ आस-पास
प्रिंट एवं वेब पोर्टल
हिन्दी प्रिंट एवं वेब पोर्टल, न्यूज ग्रुप समूह (छ.ग.)

05 लोकसभा चुनाव-2024

तीसरी बार स्कोर 10-01

कवर स्टोरी...

2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसके हाथ से बस्तर फिसल गया। यहां से विधायक कवासी लखमा हार गए हैं। वहीं राजनांदगांव से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 44 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। कोरबा एक मात्र सीट कांग्रेस के हाथ आई है। कोरबा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस की सीट दोबारा जीत दर्ज की। सबसे बड़ी जीत भाजपा को रायपुर में मिली है, भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5 लाख 75 हजार 285 वोटों से हराया है। भाजपा का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में हर सीट पर हर बार करीब 1 प्रतिशत तक बढ़ा है। सबसे ज्यादा अंतर रायपुर में आया है। इस बार 66.19 प्रतिशत वोट भाजपा को मिले हैं। वहीं कांकेर में इस बार भाजपा ने महज 0.15 प्रतिशत के अंतर से जीत हासिल की है। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक लोकसभा के लिए 5 चुनाव हो चुके हैं। 2019 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव में बीजेपी 10 और कांग्रेस एक सीट जीती थी। इस बार भी यही परिणाम रहा है। इससे पहले 2004, 2009, 2014 में भाजपा ने 10-1 से जीत दर्ज की थी। 2019 में भाजपा को नौ और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार बीजेपी ने 2019 के रिकॉर्ड में सुधार करते हुए फिर से 11 में से 10 सीटें अपने नाम कर ली हैं।

नोट : पत्रिका में प्रकाशित लेखों और फोटो के लिए **छत्तीसगढ़ आसपास** की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। संपादक की सहमति इसमें अनिवार्य नहीं है। लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं। फोटो का उपयोग सिर्फ लेखों के लिए किया गया है। पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद का न्याय क्षेत्र दुर्ग (छत्तीसगढ़) होगा।

छह माह में सीएम साय ने खुद को साबित किया

किसी भी मुख्यमंत्री के लिए छह माह के समय में कुछ कर के दिखाना आसान नहीं होता है। क्योंकि छह माह का समय तो चीजो संमझने, उसे ठीक करने मे गुजर जाता है। इसलिए छह माह में किसी सीएम से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह कोई बड़ा काम करके दिखाएंगे, कोई बडी.सफलता हासिल करके दिखाएंगे। इसी दौरान लोकसभा चुनाव हो तो और भी कुछ करने का मौका नहीं रहता है। जब तक लोकसभा चुनाव की आचार सहित लगी हुई तो विकास आदि के कार्य भी नहीं होते हैं।

छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय पीएमम मोदी व अमित शाह की खोज हैं। साय मोदी मंत्रिमंडल में काम कर चुके थे। इसलिए पीएम मोदी श्री साय को जानते थे। इसलिए जब छत्तीसगढ़ का सीएम चनने का समय आया तो पीएम मोदी व अमित शाह ने श्री साय को चुना क्योंकि वह आदिवासी, ईणानदार व काम करने वाले नेता है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी सीएम बनाने की मांग तो छग राज्य बनने के समय से की जा रही थी। लेकिन कांग्रेस व भाजपा ने आदिवासी सीएम नहीं बनाया। कांग्रेस ने अजीत जोगी व भूपेश बघेल को मौका दिया तो भाजपा ने तीन बार रमन सिंह को मौका दिया। पीएम मोदी ने ही इस बात के महत्व को समझा कि छत्तीसगढ़ को आदिवासी सीएम की जरूरत है। इसलिए उन्होंने आदिवासी सीएम के रूप में श्री साय को मौका दिया।

श्री साय को छत्तीसगढ़ का सीएम बनाया गया तो उनके सामने कई तरह की चुनौती थी। उन्हें कम समय में कई काम करने थे। पहला काम तो यही था कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव में जो वादे किए है, उसे पूरा करना । कांग्रेस सरकार गई तो वह खजाना खाली कर गई थी और साय सरकार को चुनावी वादे कुछ ही दिनों के भीतर पूरे करने थे। साय ने इसे करके दिखाया। सबसे पहले उन्होंने दो माह का किसानों का बकाया बोनस दिया। ऐसा करने से रमन सरकार पर लगा कलंक धुल गया। इसके बाद उन्होंने किसानों का धान पहले से ज्यादा और 3100 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा। किसानों को वादे के मुताबिक पहले से ज्यादा भुगतान किया। भूपेश सरकार तो चार किश्तों में किसानों को पैसा दिया करती थी, साय सरकार ने पूरा पैसा एक मुश्त देने का वादा किया था और एकमुश्त दिया भी।

इसके अलावा गरीबों को पीएम आवास, मुफ्त अनाज,महतारी वंदन योजना के तहत महिलाओं को एक हजार रुपए महीना दिया,तंदूपत्तता मानदेय बढ़ा हुआ दिया गया, शासकीय भर्ती में आयु सीमा में पांच साल की छूट दी,भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चत की, नक्सल उन्मूलन को तेज किया। रामलला के दर्शन को राज्य के लोगों को अयोध्या ले जाया गया। साय सरकार की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि साय सरकार ने वादा किया था कि मोदी की गारंटी का वादा कर छत्तीसगढ़ की सभी सीटें जीतक पीएम मोदी की झोली में डालना है।

आपका,
प्रदीप भट्टाचार्य
संपादक

सीएम व मंत्रियों का विकसित छग के विजन पर विचार मंथन

विकसित छत्तीसगढ़ विजन

नई ऊंचाईयों को छूने का संकल्प

आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर छत्तीसगढ़ एक समृद्ध और विकसित राज्य के रूप में आकार लेगा तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इस संकल्प को पूरा करने के प्रथम कदम के रूप में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और राज्य मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने विकसित छत्तीसगढ़ के विजन पर गत दिनों भारतीय प्रबंधन संस्थान रायपुर में नीति निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों के विषय विशेषज्ञों के साथ दो दिनों तक विचार मंथन किया गया। छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, खनिज और वन सम्पदा तथा कुशल मानव संसाधन से सम्पन्न राज्य है। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2047 तक विकसित राज्य बनाने के लिए विशेषज्ञों ने शासन-प्रशासन के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक तकनीकी के दक्षतापूर्ण उपयोग, नवाचार, राज्य के संसाधनों के कुशलतापूर्वक उपयोग की आवश्यकता बताई। इसे पूरा करने के लिए विकसित छत्तीसगढ़ का स्पष्ट विजन तय कर उस पर दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ना होगा। विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य, अधोसंरचना, प्राकृतिक संसाधनों के कुशल उपयोग, खनन क्षेत्र में सुधार, प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए कुशल वित्त प्रबंधन, सुशासन के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण, कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों के विकास, शिक्षा और लोगों के जीवन को आसान बनाने की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता बताई।

किन कामों में खर्च हुए करीब 300 करोड़

खनन, पर्यावरण, स्वाईल हेल्थ, विकास परियोजनाओं के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और डेटा विश्लेषण का उपयोग कर अच्छे परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, जहां सैटेलाईट मैपिंग का कार्य 1990 के दशक में हो चुका है। जियो टैगिंग ऑफ विलेज का काम पूरा होने पर जिला, तहसील, गांव, सर्वे नंबर, ऑनरशिप, क्षेत्रफल, टाइप ऑफ लैंड सहित अनेक जानकारियां एक क्लिक पर उपलब्ध हो सकेंगे, इससे नीतियों का निर्माण और परियोजनाओं का क्रियान्वयन कुशलतापूर्वक और तेजी से किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ को विकसित राज्य बनाने के लिए विजन डाक्यूमेंट बनाने का काम राज्य योजना आयोग को सौंपा गया है। उम्मीद है कि आने वाले समय में समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ राज्य जन-आकांक्षाओं को पूरा करने वाला एक हरित राज्य भी होगा।

मजबूत निगरानी और नियंत्रण तंत्र

विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार की भूमिका के संबंध में विशेषज्ञों का सुझाव था कि विकास योजनाओं के निर्माण के साथ-साथ विकसित छत्तीसगढ़ के विजन के क्रियान्वयन की निगरानी और नियंत्रण का लगातार कार्य राज्य सरकार को करना होगा। इसके लिए कुशल निगरानी तंत्र बनाने की जरूरत होगी, उन्होंने कहा कि वतर्मान में निगरानी और नियंत्रण तंत्र को और अधिक मजबूत बनाने की जरुरत है। इसके साथ ही साथ आर्थिक प्रगति के लिए राज्य की नई क्षमताएं पहचाननी होगी।

सरप्लस रिवेन्यू अर्थव्यवस्था की ताकत

साथ ही निजी क्षेत्र को परियोजनाओं में निवेश और संचालन के लिए प्रोत्साहित किया जाए। विशेषज्ञों ने छत्तीसगढ़ की बेहतर अर्थव्यवस्था का उल्लेख करते हुए कहा कि सरप्लस रिवेन्यू, अच्छा फिजिकल डिसीप्लिन, लो डेब्ट एण्ड जीडीपी रेश्यो राज्य की अर्थव्यवस्था की ताकत है। भौगोलिक रूप से देश के मध्य में स्थित छत्तीसगढ़ के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव-2024

तीसरी बार स्कोर 10-01

छत्तीसगढ़ भाजपा ने 11 में से 10 सीटें जीतीं तो वहीं कांग्रेस 2 से एक पर आई कांग्रेस

कोरबा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस की सीट दोबारा जीत दर्ज की।

छत्तीसगढ़ से सांसद चुने गए 11 में से 3 लगातार दूसरी बार लोकसभा पहुंचे हैं। इनमें दुर्ग से विजय बघेल, राजनांदगांव से संतोष पांडेय और कोरबा से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत शामिल हैं। बाकी पहली बार लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं। इनमें सरगुजा से चिंतामणी महराज, बिलासपुर से तोखन साहू, महासमंदु से रुपकुमारी चौधरी, रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल, कांकेर से भोजराज नाग पहले विधायक रह चुके हैं।

2019 में कांग्रेस ने 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार उसके हाथ से बस्तर फिसल गया। यहां से विधायक कवासी लखमा हार गए हैं। वहीं राजनांदगांव से भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 44 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव हारे हैं। कोरबा एक मात्र सीट कांग्रेस के हाथ आई है। कोरबा में नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने कांग्रेस की सीट दोबारा जीत दर्ज की।

1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा वोट पड़े

प्रदेश की 11 लोकसभा सीटों में कुल 1 करोड़ 50 लाख 23 लाख 639 मतदाताओं ने मतदान किया है। इसमें से बीजेपी को 79 लाख 9 हजार 797 वोट, कांग्रेस को 61 लाख 68 हजार 408, अदर्स को 5 लाख 99 हजार 244, बीएसपी को 1 लाख 74 हजार 910, नोटा को 1 लाख 35 हजार 430, सीपीआई को 35 हजार 850 वोट मिला है। छत्तीसगढ़ में में 'नोटा' को कुल 1 लाख 35 हजार 430 वोट मिले हैं। इस हिसाब से वह चौथे नंबर पर रहा है। मतदाताओं से मत लेने के मामले में छत्तीसगढ़ में पहले नंबर पर बीजेपी, दूसरे नंबर पर कांग्रेस, तीसरे नंबर पर बीएसपी है।

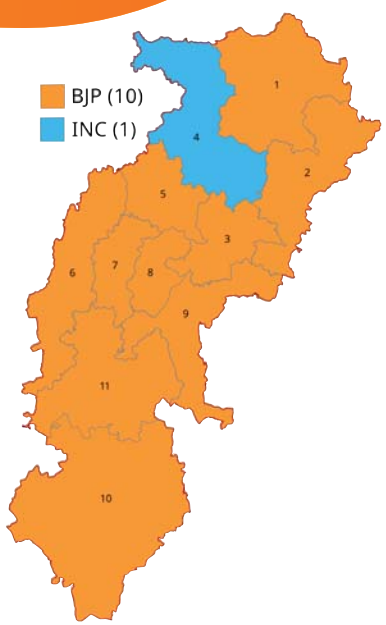

सबसे बड़ी जीत भाजपा को रायपुर में मिली है, भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5 लाख 75 हजार 285 वोटों से हराया है। भाजपा का वोट शेयर छत्तीसगढ़ में हर सीट पर हर बार करीब 1 प्रतिशत तक बढ़ा है। सबसे ज्यादा अंतर रायपुर में आया है। इस बार 66.19 प्रतिशत वोट भाजपा को मिले हैं। वहीं कांकेर में इस बार भाजपा ने महज 0.15 प्रतिशत के अंतर से जीत हासिल की है। 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक लोकसभा के लिए 5 चुनाव हो चुके हैं। 2019 के चुनाव को छोड़कर बाकी सभी चुनाव में बीजेपी 10 और कांग्रेस एक सीट जीती थी। इस बार भी यही परिणाम रहा है। इससे पहले 2004, 2009, 2014 में भाजपा ने 10-1 से जीत दर्ज की थी। 2019 में भाजपा को नौ और कांग्रेस को दो सीटें मिली थीं। लेकिन इस बार बीजेपी ने 2019 के रिकॉर्ड में सुधार करते हुए फिर से 11 में से 10 सीटें अपने नाम कर ली हैं।

0.44 फीसदी घटे कांग्रेस के वोट शेयर

छत्तीसगढ़ में विधानसभा के बाद लोकसभा का चुनाव का परिणाम भी कांग्रेस के लिए झटका देने वाला रहा। लोकसभा चुनाव 2024 में कांग्रेस के वोट शेयर में कोई विशेष अंतर नहीं आया है, बावजूद इसके कांग्रेस ने एक सीट खो दिया है। 2019 में कांग्रेस छत्तीसगढ़ में 2 सीट जीती थी, लेकिन इस बार कांग्रेस केव ल एक सीट ही हासिल कर पाई है। कांग्रेस जिस एक मात्र सीट पर जीती है वह कोरबा सीट है। माना जा रहा है कि कोरबा सीट भी कांग्रेस की वजह से नहीं बल्कि डॉ. चरणदास महंत की वजह से बची है। वरना बीजेपी छत्तीसगढ़ में क्लीन स्वीप कर जाती। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को छत्तीसगढ़ में कुल 52.65 प्रतिशत वोट मिले हैं। वहीं, कांग्रेस के हिस्से में 41.04 प्रतिशत वोट आया है। 2019 की तुलना में कांग्रेस के वोट शेयर में मात्र 0.44 प्रतिशत की कमी आई है। 2019 में कांग्रेस को 41.5 प्रतिशत वोट मिला था और कांग्रेस 2 सीट कोरबा और बस्तर जीत गई थी। इस बार कांग्रेस के वोट शेयर में केव ल आधा प्रतिशत से भी कम की कमी आई है, बावजूद इसके पार्टी के हाथ पूरी सीट निकल गई।

1.25 प्रतिशत बढ़े बीजेपी के वोट शेयर

10 सीट जीतने वाली बीजेपी के वोट शेयर में 1.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बीजेपी को कुल 52.65 प्रतिशत वोट मिला है। यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में लोकसभा चुनाव में किसी पार्टी को मिला सर्वाधिक वोट शेयर है। राज्य निर्माण के बाद से अब तक लोकसभा के पांच चुनाव हो चुके हैं। 2019 को छोड़ दें तो बाकी सभी चुनावों में बीजेपी 10 सीट जीतती रही है, लेकिन कभी बीजेपी का वोट शेयर इतना अधिक नहीं रहा है। 2004 में बीजेपी का वोट शेयर 47.8 था। 2009 में यह घटकर 45 प्रतिशत हो गया, बावजूद इसके पार्टी 10 सीट जीती। 2009 में फिर इसमें बढ़ोतरी हुई और पार्टी के हिस्से में 49.7 प्रतिशत वोट शेयर आया। 2019 में बीजेपी 9 सीट जीती, लेकिन उसका वोट शेयर बढ़कर 51.4 प्रतिशत हो गया था। इस बार फिर इसमें बढ़ोतरी हुई है। रायपुर में सबसे बड़ी जीत, कांकेर में सबसे छोटी जीत लोकसभा चुनाव में भाजपा को सबसे बड़ी जीत रायपुर में मिली है। भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल ने कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5 लाख 75 हजार 285 वोटों के अंतर से हराया है। जीत का यह अंतर कांग्रेस प्रत्याशी को मिले कुल वोटों (475066) से भी ज्यादा है।

दुर्ग के दबंग बने विजय

4 लाख 38 हजार 226 वोटों के बड़े अंतर से जीते विजय बघेल

कभी कांग्रेस की पारंपरिक सीट रही दुर्ग अब भाजपा के लिए अजेय दुर्ग बनती जा रही है। भाजपा के विजय बघेल ने अपनी जीत को दोहराते हुए बड़े मार्जिन 4 लाख 38 हजार 226 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र साहू को हराया। विजय बघेल को 9 लाख 56 हजार 497 वोट मिले। राजेंद्र साहू को 5 लाख 18 हजार 271 वोट मिले। इस तरह जीत का अंतर 4 लाख 38 हजार 226 रहा। कांग्रेस ने राजेंद्र साहू को टिकट देकर जो साहू ट्रंप कार्ड खेला था, वह यहां काम नहीं आया। छत्तीसगढ़ की हाइप्रोफाइल सीट पर इस बार कांग्रेस ने यहां जाति समीकरण के आधार पर केंद्रीय सहकारी बैंक दुर्ग के अध्यक्ष राजेंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया था। दुर्ग लोकसभा में साहू समाज का वोट बैंक काफी अधिक है, इसलिए ऐसा लग रहा था कि भाजपा प्रत्याशी को बड़ी चुनौती मिलेगी, लेकिन विजय बघेल के काम और सरल सहज मिलनसार मिजाज ने साहू फैक्टर को भी फेल कर दिया और वो पिछली बार से भी अधिक मतों से विजयी हुए। भूपेश बघेल अपने ही विधानसभा से राजेंद्र साहू को लीड नहीं दिला सके। भाजपा को पाटन इलाके से कांग्रेस प्रत्याशी से 24643 वोट अधिक मिले। दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कुल 20 लाख 90 हजार 414 मतदाता हैं, जिनमें से 73.68 फीसदी यानी 15,40,193 मतदाताओं ने मतदान किया था।

सदैव करते रहेंगे जनता की सेवा: विजय

दुर्ग में बड़े अंतर से जीत के बाद नवनिर्वाचित सांसद विजय बघेल ने कहा कि वे सदैव जनता की सेवा करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि मोदीजी का संकल्प है, उसे पूरा करने में जनता ने जो विश्वास जताया है, वे उस विश्वास को सदा बनाए रखेंगे। विजय बघेल ने कहा कि भाजपा के ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता, जिन्होंने 44-45 डिग्री के तापमान में भी जिले के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ लगन से मेहनत की। पूरी आत्मीयता और कर्मठता से लगे रहे, इसी का प्रतिफल है कि मोदीजी के संदेशों को घर-घर पहुंचाया जा सका और दुर्ग में इतनी बड़ी जीत मिली। उन्होंने कहा कि जनता ने एक लाख के वादे को छोड़ एक हजार की रकम पर भरोसा जताया है।

जीते : विजय बघेल
9,56,497
वोट मिले

हारे : राजेन्द्र साहु
5,18,271
वोट मिले

2019 में भाजपा के विजय बघेल 3,91,978 वोटों से जीते थे।

अब संतोष पांडेय का राज

कांग्रेस की प्रतिष्ठा से जुड़ी सीट से पूर्व मुख्यमंत्री को हराया

राजनांदगांव लोकसभा सीट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मैदान में उतरने से ये सीट प्रदेश की सबसे हाईप्रोफाइल सीट हो गई थी। मोदी मैजिक और ध्रुवीकरण में भूपेश जैसे दिग्गज को हारना पड़ा और संतोष पांडेय दोबारा सांसद बनने में कामयाब हुए। कांग्रेस की प्रतिष्ठा से भी जुड़ी इस सीट पर रायपुर से दिल्ली तक नजर थी। पूर्व मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र से दूसरी बार चुनाव लड़ रहे सांसद संतोष पांडेय ने 44 हजार 411 वोटों से जीत दर्ज की है। उन्होंने भूपेश बघेल को 44 हजार 411 वोटों से हराया। संतोष पांडेय को 7 लाख 12 हजार 57 वोट मिले, वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल को 6 लाख 67 हजार 646 वोट मिले हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बहुत मेहनत की, लेकिन जनता ने सांसद संतोष पांडेय को फिर चुन लिया। संतोष पांडेय के खिलाफ एंटी इंकमबेंसी थी। लेकिन यहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण और मोदी के चेहरे ने काम किया। भूपेश बघेल के बाहरी प्रत्याशी होने के कारण पुराने कांग्रेसियों को यह चिंता सता रही थी कि बघेल एक बार यहां से जीत गए, तो हमेशा के लिए उनकी सीट सुरक्षित हो जाएगी। फिर हमारा क्या होगा। यह हार का सबसे बड़ा कारण रहा है। इस सीट से 9 बार कांग्रेस, 8 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी जीत चुकी है।

देवतुल्य मतदाताओं ने दिलाई जीतः संतोष

नवनिर्वाचित सांसद संतोष पांडे ने जीत के बाद कहा कि ये जीत आम कार्यकर्ता देव तुल्य मतदाताओं के कारण मिली है। मैं अपने प्रयास से राजनांदगांव के विकास के लिए केंद्रीय योजनाओं का सुचारू रूप से संचालन करते हुए जन-जन तक पहुंचाने का काम करूंगा। उन्होंने कहा कि भूपेश बघेल जो एक पूर्व मुख्यमंत्री है मुश्किल से चार महीना उनको इस प्रदेश से मुख्यमंत्री पद से हटे हुए हुआ है। वो राजनांदगांव ये सोचकर आए थे कि यहां कांग्रेस ने 5 सीट विधानसभा में जीती है, तो मैं भी यहां आसानी से जीत जाउंगा। लेकिन उनका सपना अधूरा रह गया और मोतीलाल वोरा के जैसे उन्हें वापस होना पड़ेगा। संतोष पांडे ने कहा कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है यहां किसी भी सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट मिलता है तो उसके पीछे पूरी संगठन शक्ति लग जाती है।

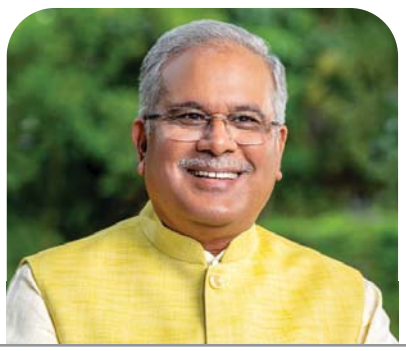

हारे : भूपेश बघेल
6,67,646
वोट मिले

जीते : संतोष पांडेय
7,12,057
वोट मिले

2019 में भाजपा के संतोष पांडेय 1,11,966 वोटों से जीते थे।

तोखन साहू के सिर ताज

1,64,558 वोटों से देवेंद्र यादव को हराकर बने सांसद

बिलासपुर सीट से बीजेपी को 8वीं बार जीत मिली है। भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने बिलासपुर लोकसभा से लगभग 1 लाख 64 हजार 558 मतों से जीत दर्ज की है। तोखन साहू को कुल 724937 मत मिले हैं। वहीं कांग्रेस के देवेन्द्र यादव को 560379 वोट मिले हैं। साहू वर्सेस यादव के कारण यह सीट चर्चा में आई बिलासपुर सीट में साहू के बाद यादव वोटर्स की बहुलता है। इसी कारण कांग्रेस से भिलाई के विधायक देवेन्द्र यादव को बिलासपुर शिफ्ट किया गया। देवेन्द्र ने बहुत कम समय में शानदार चुनाव लड़ा, लेकिन जीत नहीं पाए। देवेन्द्र ने ईवीएम बदलने की भी शिकायत की, जिसे निर्वाचन अधिकारी ने नकार दिया। उधर, तोखन साहू मुंगेली क्षेत्र से आते हैं। दिलीप सिंह जूदेव को छोड़ दें, तो ज्यादातर सांसद मुंगेली क्षेत्र से ही रहे हैं। यहां अगर रामशरण यादव चुनाव लड़ते तो शायद स्थिति थोड़ी अलग हो सकती थी, लेकिन वे विधानसभा चुनाव में टिकट खरीद-बिक्री वाले ऑडियो टेप में ट्रैप हो गए। यहां मोदी फैक्टर तो था ही, साथ ही डिप्टी सीएम अरुण साव और चार लोकसभा के क्लस्टर हेड अमर अग्रवाल के लिए भी प्रतिष्ठा का प्रश्न था। अरुण साव मुंगेली से ही विधायक हैं और अमर अग्रवाल को बिलासपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा लोकसभा क्लस्टर की जिम्मेदारी दी गई थी।

विकसित बिलासपुर बनाएंगे: तोखन साहू

तोखन साहू ने जीत की श्रेय पार्टी और कार्यकर्ताओं को दिया है। देशभर में 'मोदी की गारंटी' पर लोगों का जनादेश मिला है। मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पार्टी ने मेरी उम्मीद से दोगुना अवसर दिया है। मेरी प्राथमिकता बिलासपुर को विकास के शीर्ष पटल पर पहुंचाना है। बिलासपुर और मुंगेली क्षेत्र की जनता की बहुप्रतीक्षित मांग उसलापुर से मुंगेली होते डोंगरगढ़ रेल लाइन की प्राथमिकता है। इसका जल्द ही काम का असर देखने को मिलेगा। साथ ही आम जनमानस के मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र में पानी, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के विस्तार और चकरभाटा एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग जैसी मांगों को पूर्ण करने का लक्ष्य जाहिर किया है।

जीते : तोखन साहू
7,24,937
वोट मिले

हारे : देवेन्द्र यादव
5,60,379
वोट मिले

2019 में भाजपा के अरुण साव 1,41,763 वोटों से जीते थे।

राधेश्याम राठिया का राज

कांग्रेस प्रत्याशी डॉ मेनका देवी सिंह को 2,40,391 मतों से हराया

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी राधेश्या म राठिया ने कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मेनका देवी सिंह को 2,40,391 मतों से हराया है। 24 राउंड की मतगणना में भाजपा को 8 लाख 8275 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी डॉ. मेनका देवी को 5 लाख 67 हजार 884 वोट मिले हैं। वहीं, डाकमत में भाजपा प्रत्याशी को 1608 और कांग्रेस प्रत्याशी को 1397 वोट मिले हैं। भाजपा की जीत की वजह पूर्व में रायगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद रहे विष्णुदेव साय का अब प्रदेश का मुख्यमंत्री होना है। जिसकी वजह से जनता ने फिर से पार्टी पर अपना विश्वास जताया है। भाजपा प्रत्याशी का नया चेहरा नहीं था और लगातार वे लोगों के संपर्क में थे। राधेश्या म की जीत में रायगढ़ विधायक के साथ ही स्थानीय भाजपा के अन्य नेताओं और कार्यकर्ताओं की मेहनत भी है, जो लगातार भाजपा के जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर लोगों के पास पहुंच रहे थे। वहीं, विधानसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में भी करारी हार का सामना करना पड़ा है। पार्टी ने इस बार रायगढ़ जिला मुख्यालय को छोड़ नए नवगठित सारंगढ़ जिले से 25 सालों बाद राजपरिवार की सदस्य मेनका सिंह को मुकाबले में उतारा था। जिसकी वजह से पार्टी के भीतर गुटबाजी दिखी और स्थानीय कांग्रेस नेताओं ने जमीनी स्तर पर जीत के लिए कोई प्रयास और जनसंपर्क नहीं किया।

जीत का श्रेय कार्यकर्ताओं को : राधेश्याम राठिया

नवनिर्वाचित सांसद राधेश्याम राठिया का कहना है कि सबसे पहले तो मैं रायगढ़ की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इन्होंने मुझे जिताया। उन्होंने कहा कि वे अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करेंगे। अब मेरी प्राथमिकता होगी कि रायगढ़ में टर्मिनल, हवाई अड्डा, सारंगढ़ जो रेलवे से अछूता है, उसे पूरा करना। जशपुर को भी रेल लाइन से जोड़ना और पर्यटन क्षेत्र में बढ़ावा देना है। मैं जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा। साथ ही जो भी प्रमुख समस्या है, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। तथा कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण, और आशीर्वाद के बिना मेरा चुनाव में विजय संभव नही था। यह जीत आप सभी की है और इस जीत ने हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है।

हारे : मेनका सिंह
5,67,884
वोट मिले

जीते : राधेश्याम राठिया
8,08,275
वोट मिले

2019 में भाजपा की गोमती साय 66,027 वोटों से जीती थीं।

रुपकुमारी के सिर सजा ताज

पूर्व कैबिनेट मंत्री ताम्रध्वज साहू को 1 लाख 45 हजार 456 वोटों से हराया

छत्तीसगढ़ के महासमंदु लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी रूपकुमारी चौधरी ने बाजी मारी है। उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू को एक लाख 45 हजार 456 वोटों से पूर्व मंत्री को हराया है। रूपकुमारी चौधरी सात लाख तीन हजार 659 वोट मिले। वहीं ताम्रध्वज साहू सरपंच से लेकर विधायक और सांसद तक का सफर तय कर चुके कांग्रेस प्रत्याशी ताम्रध्वज साहू पांच लाख 58 हजार 203 मिले। पहले चरण से ही भाजपा की प्रत्याशी ने ताम्रध्वज साहू को पीछे कर दिया था। जिला पंचायत, भाजपा जिला महामंत्री और महिला मोर्चा के पद पर रह चुकी रुपकुमारी 2013 से 2018 तक बसना से विधायक भी रहीं। ओबीसी वर्ग के दबदबे वाली इस सीट से कांग्रेस ने ताम्रध्वज साहू को इसलिए उतारा था कि उसे साहू वर्ग का समर्थन मिलेगा। लेकिन वोटों का पलड़ा रुपकुमारी की ओर ज्यादा झुक गया। विद्याचरण शुक्ल, श्यामाचरण शुक्ल और अजीत जोगी जैसे दिग्गज नेताओं के इस सीट पर 1952 से अब तक हुए कुल 19 चुनाव हुए। जिनमें से 12 बार कांग्रेस का कब्जा रहा है। वहीं साल 2009, 2014 और 2019 के बाद अब 2024 में भाजपा ने जीत दर्ज की है। महासमुंद सीट से पहली बार कोई महिला संसद पहुंची हैं।

जीत ने बढ़ाई हमारी जिम्मेदारी : रुपकुमारी

नवनिर्वाचित सांसद रुपकुमारी चौधरी ने कहा है कि जीत का श्रेय जनता और पार्टी के शीर्ष नेताओं को दिया है। उन्होंने कहा कि लोकसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को आगे बढ़ाएंगे। रूपकुमारी ने केंद्रीय व राज्य नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि, जो जिम्मेदारी उसे जनता ने जीत दिलाकर सौपी है उसे विकास के रास्ते वो पूरा करेगी। और लोकसभा के अंतर्गत आने वाले महासमंदु , गरियाबंद और धमतरी जिले की जो भी मांगें है उसे केंद्र के सामने रखकर पूरा करेंगी। इसके लिए वो पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत, समर्पण, और आशीर्वाद के बिना मेरा चुनाव में विजय संभव नही था। यह जीत आप सभी की है और इस जीत ने हमारी जिम्मेदारी और बढ़ा दी है।

जीते : रुपकुमारी चौधरी
7,03,659
वोट मिले

हारे : ताम्रध्वज साहू
5,58,203
वोट मिले

2019 में भाजपा के चुन्नी लाल साहू 90511 वोटों से जीते थे।

कमलेश ने खिलाया कमल

8 विधानसभाओं में विधायक होने के बाद भी हारे शिव डहरिया

जांजगीर चांपा लोकसभा सीट पर भाजपा ने पांचवी बार अपना कब्जा जमा लिया है। मोदी लहर में कमलेश जांगड़े ने 60 हजार वोटों से पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया को पछाड़ा। भाजपा प्रत्याशी कमलेश जांगड़े को 6 लाख 78 हजार 199 वोट मिले। कांग्रेस प्रत्याशी शिव कुमार डहरिया को 6 लाख 18 हजार 199 वोट मिले हैं। 8 विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक होने के बाद भी हार मिली। हालांकि जीत का मार्जिन महज 4.31 फीसदी ही है। सीट बनने के बाद 1957 में हुए पहले चुनाव से लेकर अब तक 10 बार कांग्रेस, 5 बार भाजपा और 1 बार जनता पार्टी जीती है। भाजपा की जीत के पीछे छह महीने की विष्णुदेव साय की सरकार में अधिकांश मोदी की गारंटी का पूरा हो जाना है। तो वहीं मोदी के चेहरे और राम मंदिर निर्माण, धारा 370 हटना, हिंदुत्व का मुद्दा भी भाजपा के लिए फायदेमंद रहा। वहीं सरपंच रहीं कमलेश जांगड़े का सरल सहज और मिलनसार महिला प्रत्याशी होना भी उन्हें वोट मिलने का कारण बना। 8 विधानसभा क्षेत्र वाली लोकसभा सीट में कमलेश जांगड़े ने घनघओर जनसंपर्क करते हुए जनता के पास पहुंचीं। वहीं कांग्रेसियों में अंतर्कलह से चुनाव के बीच में कांग्रेस के नेताओं का पार्टी छोड़ना और 8 विधानसभा के विधायकों का सक्रिय नहीं होना कांग्रेस के हार की प्रमुख वजह रही।

ये जीत जनता जनार्दन की : कमलेश जांगड़े

नवनिर्वाचित सांसद कमलेश जांगड़े ने अपनी जीत के लिए बीजेपी के शीर्ष नेताओं के साथ कार्यकर्त्ताओं और जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में जांज गीर से भले ही कांग्रेस के 8 विधायकों को जीत मिली लेकिन इस बार जनता ने उन्हें नकार दिया और मोदी पर भरोसा जताते हुए बीजेपी को जीत दिलाई है। कमलेश जांगड़े ने कहा कि ये जीत जनता जनार्दन और कार्यकर्ताओं के अलावा केंद्रीय और राज्य स्तरीय नेताओं की जीत है। हम शुरू दिन से जीत को लेकर आश्वस्त थे और सबका साथ सबका विकास हमारा नारा रहा है। आगे भी हम सबको साथ लेकर विकास ओर बढ़ेंगे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी डा. शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है, उसे हम स्वीकार करते हैं।

हारे : डॉ. शिवकुमार डहरिया
6,18,199
वोट मिले

जीते : कमलेश जांगड़े
6,78,199
वोट मिले

2019 में भाजपा के गुहाराम अजगले 83,255 वोटों से जीते थे।

भोजराज का बदला भाग्य

जीत-हार के मार्जिन से ज्यादा है नोटा का वोट

कांकेर लोकसभा सीट में सबसे कम वोटों से हार-जीत का फैसला हुआ। भाजपा के भोजराज नाग ने कांग्रेस प्रत्याशी बीरेश ठाकुर को महज 1884 वोटों से हराया है। इससे ज्यादा वोट नोटा को मिले हैं। कांकेर लोकसभा सीट से दूसरी बार अपनी किस्मत आजमा रहे कांग्रेस प्रत्याशी बिरेश ठाकुर फिर हार गए। वे अपने प्रतिद्वंदी बीजेपी प्रत्याशी भोजराज नाग से 1884 वोटों से पराजित हुए हैं। भोजराज नाग को 5 लाख 97 हजार 624 वोट और बिरेश ठाकुर को 5 लाख 95 हजार 740 वोट मिले हैं।

बिरेश ने 1800 डाक मतपत्र रिजेक्ट करने का आरोप लगाया और रिकाउंटिंग की मांग की। हालांकि बाद में भोजराज नाग को विजयी घोषित किया गया। 2019 में भी बिरेश ठाकुर कांकेर से कांग्रेस प्रत्याशी थे। इस चुनाव में वे 6914 वोटों से अपने प्रतिद्वंदी मोहन मंडावी से चुनाव हारे थे। दिलचस्प बात ये है कि कांकेर लोकसभा सीट पर नोटा को 18669 वोट मिले, जबकि बिरेश की हार का मार्जिन 1884 था, जो नोटा के कुल वोट से लगभग 10 गुना कम रहा। 1967 से अब तक हुए चुनावों में 6 बार कांग्रेस, 7 बार भाजपा, जनसंघ और जनता पार्टी ने 1-1 बार जीत दर्ज की है।

डबल इंजन की सरकार से होगा विकास : भोजराज

कांकेर लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद भोजराज नाग ने कहा कि सीएम ने जो रणनीति कांकेर लोकसभा सीट पर जीत के लिए बनाई थी वो कारगर साबित हुई। उनके दिशा निर्देश में कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसका नतीजा जीत के तौर पर हमें मिला। छत्तीसगढ़ में डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार के चलते छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास का काम हो रहा है। भोजराज नाग ने कहा कि केंद्र और राज्य की योजनाओं का फायदा जनता को मिला। इसीलिए उसने हमें प्रचंड बहुमत से जिताया। कम मार्जिन से जीत के सवाल पर वे कहते हैं कि कांकेर सीट की भौगोलिक स्थिति ऐसी है, जिसकी वजह से वोट परसेंट कम हुए हैं। हालांकि कांकेर लोकसभा सीट हमेशा से बीजेपी की परंपरागत सीट रही है।

जीते : भोजराज नाग
5,97,624
वोट मिले

हारे : बीरेश ठाकुर
5,95,740
वोट मिले

2019 में भाजपा के मोहन मंडावी 6914 वोटों से जीते थे।

बस्तर के बाजीगर बने महेश

कर्मा और बैज के गढ़ में चला महेश कश्यप का मैजिक

बस्तर को एक बार फिर भाजपा ने कांग्रेस से छीन लिया है। छत्तीसगढ़ के बस्तर को 13 वें सांसद के रुप में भाजपा के महेश कश्यप मिल गए हैं। महेश कश्यप ने 55 हजार 245 वोटों से कवासी लखमा को शिकस्त दी है। यहां की जनता ने आजादी के बाद निर्दलीय लेकर कांग्रेस-भाजपा और अन्य दलों पर भरोसा जताया है। हालांकि 1952 से लेकर अब तक कांग्रेस-भाजपा 6-6 बार, 5 बार निर्दलीय और 1 बार जनता पार्टी ने जीती है। 2019 में कांग्रेस के दीपक बैज इस सीट को अपने कब्जे में किए थे, लेकिन अब महेश ने यह सीट फिर से भाजपा की झोली में डाल दी है। दरअसल, महेश कश्यप विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य थे। बस्तर में धर्मांतरण के मसले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहते थे। वहीं इस लोकसभा चुनाव भाजपा ने महेश पर दांव खेला और परिणाम पक्ष में आया। खास बात रही कि इनके सामने कांग्रेस के सबसे मजबूत कवासी लखमा थे। कवासी लखमा कोंटा विधानसभा से लगातार 6 बार के विधायक हैं। एक तरफ जहां लखमा का राजनीतिक अनुभव अधिक था तो वहीं दूसरी तरफ महेश कश्यप नए खिलाड़ी थे। लेकिन उन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की। दंतेवाड़ा विधानसभा जिसे कांग्रेस के दिवंगत नेता महेंद्र कर्मा और कर्मा परिवार का गढ़ माना जाता है, लेकिन यहीं से कांग्रेस पीछे रही।

संसद में उठाएंगे बस्तर की आवाज : महेश

नवनिर्वाचित सांसद महेश कश्यप ने कहा कि मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों ने मुझ जैसे गरीब किसान के बेटे पर भरोसा जताया और सांसद बनाया। उन्होंने कहा कि मैं बस्तर लोकसभा के विकास के लिए संसद तक बस्तरवासियों की आवाज को पहुंचाउंगा। उन्होंने कहा कि फिर से मोदी जी और भाजपा पर भरोसा जताकर जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, उसके लिए क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अब दंतेवाड़ा में भी डबल इंजन की सरकार है। जो कमी बस्तर से रह गयी थी, वो पूरी करके जनता ने उन्हें विजयी बनाकर आशीर्वाद दिया है। अब क्षेत्र का विकास डबल इंजन होने के कारण तीव्रगति से होगा।

हारे : कवासी लखमा

4,03,153

वोट मिले

जीते : महेश कश्यप

4,58,398

वोट मिले

2019 में कांग्रेस के दीपक बैज 38,982 वोटों से जीते थे।

चमके चिंतामणि महाराज

दलबदल के बावजूद जनता ने दिया महाराज को आशीर्वाद

सरगुजा लोकसभा क्षेत्र से चिंतामणि महाराज करीब 64 हजार 585 मतों से चुनाव जीत गए हैं। चुनाव से पहले वह कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। उन्होंने कांग्रेस की शशि सिंह को हराया। सरगुजा लोकसभा में यह भाजपा की लगातार पांचवीं जीत है। लेकिन पिछले चार लोकसभा चुनाव के मुकाबले में यह वोट का अंतर सबसे कम हैं। बीजेपी के चिंतामणि महाराज को 7 लाख 13 हजार 200 वोट मिले। वहीं कांग्रेस से शशि सिंह को 648378 वोट मिले। सरगुजा लोकसभा अंतर्गत आने वाले 8 विधानसभाओं में से पांच में भाजपा और तीन में कांग्रेस को बढ़त मिली है। रामानुजगंज, अंबिकापुर, लुंड्रा, प्रेमनगर, भटगांव विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को बढ़त मिली। साथ ही सीतापुर, सामरी और प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को बढ़त मिली है। सरगुजा लोकसभा सीट पर तीसरे चरण में 07 मई को वोटिंग हुई थी। जिसमें 79.89 फीसदी मतदान हुआ है। 1952 में अस्तित्व में आई इस सीट पर पिछले 20 सालों से बीजेपी का कब्जा है। भाजपा ने अपनी मौजूदा सांसद रेणुका सिंह की टिकट काटकर चिंतामणि महाराज को उम्मीदवार बनाया था। चिंतामणि महाराज बीजेपी की उम्मीदों पर खरे उतरे और वे पार्टी के परचम फहराने में कामयाब हुए।

सबकी अपेक्षाओं पर खरा उतरुंगा : चिंतामणि

नवनिर्वाचित सांसद चिंतामणि महराज ने जीत के बाद कहा कि वे पूरा प्रयास करेंगे की क्षेत्र की जनता के लिए उपलब्ध रहें। उन्होंने जीत का श्रेय क्षेत्र की जनता और भाजपा के शीर्ष और स्थानीय नेतृत्व को देते हुए कहा कि सरगुजा सांसद के रूप में दिल्ली की संसद में बैठेंगे और आदिवासी बहुल सरगुजा अंचल में विकास की गति को आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि सरगुजा संसदीय क्षेत्र के विकास में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा. रेल, हवाई और सड़क मार्ग का विकास करना प्रमुख काम होगा। चिंतामणि महराज ने कहा कि मैं भरोसा दिलाता हूं कि आप सब की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हमेशा प्रयासरत रहूंगा। मैं जीत का श्रेय हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहूंगा।

जीते : चिंतामणि महाराज
7,13,200
वोट मिले

हारे : शशि सिंह
6,48,378
वोट मिले

2019 में भाजपा की रेणुका सिंह 1,57,873 वोटों से जीती थीं।

ज्योत्सना महंत का मैजिक

लगातार दूसरी बार चुनाव जीतने में कामयाब हुई ज्योत्सना महंत

यही एक मात्र सीट है, जो कांग्रेस के खाते में गई है। कोरबा लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत्सना महंत ने 43 हजार 283 वोटों से दूसरी बार जीत दर्ज की है। कांग्रेस को 5 लाख 70 हजार 183 वोट मिले हैं। वहीं, बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडेय को 5 लाख 26 हजार 899 वोट मिले हैं। 27 प्रत्याशियों के लिए 7 मई को 75.63% वोटिंग हुई। ज्योत्सना महंत ने भाजपा की कद्दावर महिला नेता सरोज पांडेय को हराया है। ज्योत्सना महंत का कई इलाके मे काफी विरोध था। उनकी निष्क्रियता और संसदीय इलाके की सुध न लेने पर कांग्रेस के लोग भी खुश नहीं थे। बावजूद इसके ज्योत्सना महंत के पति चरणदास महंत ने ऐसी चक्रव्यूह बनाई कि सरोज पाण्डेय उसे भेद नहीं पाईं। कोरबा में वास्तविक लड़ाई सरोज पांडेय और चरणदास महंत के बीच थी। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब रहीं। पिछली बार जब प्रचंड मोदी लहर थी, तब भी वे यहां से जीती थीं। इस बार सरोज पांडेय को भिलाई से ले जाकर कोरबा सीट से लड़ाया गया। सरोज पांडेय भाजपा की राष्ट्रीय नेता हैं। वे यहां से चुनाव जीत जातीं, तो केंद्र में बड़ा ओहदा होता। सरोज पांडेय को बाहरी प्रत्याशी होने का नुकसान उठाना पड़ा। ऐसी चर्चा है कि पार्टी के ही कई दिग्गज नहीं चाहते थे कि सरोज चुनाव जीतें।

जनता के आशीर्वाद से जीती लड़ाई : ज्योत्सना

कोरबा लोकसभा क्षेत्र से दूसरी बार सांसद चुनी गईं ज्योत्सना महंत प्रदेश की इकलौती कांग्रेस सांसद हैं। 43 हजार 283 वोटों से सरोज पांडे को हराने के बाद उन्होंने कहा कि जनता के आशीर्वाद के बिना यह कठिन लड़ाई जीतना संभव नहीं था, हमने मिलकर सब के सहयोग से कार्यकर्ताओं के बलबूते यह चुनाव जीता है, यह जीत समस्त कार्यकर्ताओं और कोरबा लोकसभा क्षेत्रवासियों को समर्पित है। भरोसा जताए जाने पर सांसद ज्योत्सना चरणदास महंत ने लोकसभा क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताया है। वहीं कोरबा लोकसभा में हार को लेकर मरवाही से बीजेपी विधायक प्रणव मरपच्ची ने कहा कि इसकी समीक्षा की जाएगी। मरवाही विधानसभा में 18000 से अधिक वोटों से भाजपा की हार को संगठन की कमी बताया है।

जीते : ज्योत्सना महंत
5,70,182
वोट मिले

हारे : सरोज पांडेय
5,26,899
वोट मिले

2019 में कांग्रेस की ज्योत्सना महंत 26,349 वोटों से जीती थीं।

लोकसभा चुनाव 2024 : छत्तीसगढ़ के परिमाण

10 सीटों पर खिला कमल

2024 के नतीजे

भाजपा	कांग्रेस
10	01

सबसे अधिक 5,75,285 मतों के अंतर से जीते 'बृजमोहन अग्रवाल'

दुर्ग

विजय बघेल

राजनांदगांव

संतोष पांडेय

रायगढ़

राधेश्याम राठिया

बिलासपुर

तोखन साहु

सरगुजा

चिंतामणि महराज

बस्तर

महेश कश्यप

कांकेर

भोजराज नाग

महासमुंद

रूपकुमारी चौधरी

जांजगीर-चांपा

कमलेश जांगड़े

कोरबा

ज्योत्सना महंत

कोरबा सीट से कांग्रेस की ज्योत्सना महंत दूसरी बार जीती

रायपुर लोकसभा सीट

बृजमोहन ने रचा इतिहास

35 साल विधायकी के बाद अब बने सांसद

रायपुर लोकसभा चुनाव में भाजपा प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल ने जीत का इतिहास रच दिया। लोकसभा चुनाव में 17 लाख 69 हजार 671 वोट पड़े। इसका लगभग 60 प्रतिशत यानी 10 लाख 50 हजार 351 वोट अकेले बृजमोहन ले गए। उन्होंने करीब पौने छह लाख वोटों के अंतर से कांग्रेस उम्मीदवार विकास उपाध्याय को हराया। रायपुर में इस बार सबसे ज्यादा 38 उम्मीदवार मैदान में किस्मत आजमा रहे थे। यह सीट भाजपा का गढ़ मानी जाती है। 1996 से अब तक 9 लोकसभा चुनाव हुए। कांग्रेस ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा लेकिन हर दांव फेल हुआ। लेकिन भाजपा का किला हर चुनाव में मजबूत होता गया। हर चुनाव में जीत का अंतर बढ़ता ही गया। इस बार भाजपा ने कैबिनेट मंत्री बृजमोहन अग्रवाल को मैदान में उतारा और उन्होंने प्रदेश में जीत का रिकॉर्ड बना दिया। 1952 से अब तक कांग्रेस-भाजपा ने 8-8 और जनता पार्टी ने 1 बार जीत दर्ज की है।

बृजमोहन अग्रवाल	विकास उपाध्याय	जीत का अंतर
10,50,351 वोट मिले	4,75,066 वोट मिले	5,75,285 वोट मिले

2019 में भाजपा के सुनील सोनी 3,48,238 वोटों से जीते थे।

तोखन साहू बने आवास और शहरी विकास राज्यमंत्री

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ संभालेंगे जिम्मेदारी, मोदी मंत्रिमंडल में हुआ विभागों का बंटवारा

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सांसद तोखन साहू को मोदी मंत्रिमंडल में राज्यमंत्री बनाया गया है। उन्हें आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय में जिम्मेदारी दी गई है। कैबिनेट मंत्री मनोहर लाल खट्टर के पास ये मंत्रालय है। केंद्र में राज्यमंत्री बनने वाले तोखन साहू 7वें सांसद हैं। वो पहली बार ही लोकसभा का चुनाव जीतकर सांसद बने हैं।

मोदी सरकार के विभागों का बंटवारा कर दिया गया है। शपथ ग्रहण के 23:30 घंटे बाद विभागों का बंटवारा हुआ। बीते 9 जून को मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इनमें 30 कैबिनेट मिनिस्टर और 5 स्वतंत्र प्रभार मंत्री और 36 राज्य मंत्री हैं। तोखन साहू ने पहली बार लोकसभा की दहलीज पर कदम रखा तो वहां पर प्रवेश द्वार की सीढ़ियों को दंडवत प्रणाम किया था। वे एक बेहद साधारण किसान परिवार से आते हैं, जो कि वर्ष 2013 में पहली बार लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव में तोखन साहू ने कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव को लगभग 1 लाख 64 हजार से भी अधिक वोटों के अंतर से हराया है।

तोखन साहू ने पंच से संसद तक का तय किया सफर...

बिलासपुर लोकसभा सीट से भाजपा ने लोरमी के पूर्व विधायक तोखन साहू को अपना उम्मीदवार बनाया था। तोखन साहू ने इस सीट से ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। लोरमी के छोटे से गांव सूरजपुरा से 1994 में पंच पद से अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की। तोखन साहू क्षेत्र में काफी लोकप्रिय जनप्रतिनिधि के तौर पर जाने जाते हैं।

2013 में लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित

तोखन पंच से सरपंच, फिर जनपद सदस्य उसके बाद वर्ष 2013 में लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित हुए थे। वर्ष 2015 में विधायक रहते हुए उन्हें रमन सिंह के कार्यकाल में संसदीय सचिव का पद भी दिया गया था। वहीं कुछ ही कुछ माह पहले तोखन साहू को छत्तीसगढ़ भाजपा के किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया गया है।

2013 में लोरमी विधानसभा सीट से विधायक निर्वाचित

- 1994 से राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर लोरमी ब्लॉक के सुरजपुरा गांव के निर्विरोध पंच बने।
- 2005 में ब्लॉक लोरमी क्षेत्र क्रमांक-18 फुलवारीकला से जनपद सदस्य बने।
- 2010 को महिला आरक्षण के चलते पत्नी लीलावती साहू जनपद सदस्य बनीं
- 2010 को उनकी पत्नी लोरमी जनपद पंचायत की अध्यक्ष भी बनीं
- 2012 में जिला सहकारी बैंक बिलासपुर के प्रतिनिधि बने। जिला साहू समाज के संरक्षक, भाजपा पश्चिम मंडल के महामंत्री बने।
- 2013 में वे भाजपा के टिकट पर लोरमी विधानसभा से विधायक बने।
- 2014 में छत्तीसगढ़ वन्य जीव बोर्ड के सदस्य बने।
- 2015 में कृषि, मछली पालन, पशुपालन, जल संसाधन विभाग के संसदीय सचिव बने।
- 2015 में खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय के सदस्य बने।
- 2018 में भाजपा ने दोबारा लोरमी विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन धर्मजीत से हार गए।
- 2023 के विधानसभा चुनाव में बेमेतरा जिले की नवागढ़ विधानसभा के प्रभारी रहे थे। वर्तमान में प्रदेश भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष हैं।

1996 से बीजेपी का कब्जा, कांग्रेस ने किया था तंज-यहां म्यूट सांसद

28 साल में पहली बार बिलासपुर को मिला केंद्रीय राज्यमंत्री

2024 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भी इस बात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, 'बिलासपुर 30 साल से नेतृत्व विहीन रहा, यहां के सांसद म्यूट सांसद बनकर काम करते रहे हैं।' बड़ी बात यह कि, इस बार मंत्री पद पहली बार जीतकर संसद पहुंचे तोखन साहू को मिला है।

छत्तीसगढ़ की बिलासपुर लोकसभा सीट से पहली बार सांसद चुने गए तोखन साहू अब केंद्र में राज्यमंत्री हैं। प्रदेश से भाजपा की सरकार में राज्यमंत्री बनने वाले वे 7वें सांसद हैं। खास बात यह है कि, 28 साल बाद बिलासपुर के खाते में केंद्र का मंत्री पद गया है। वो भी तब, जब 1996 से यह सीट भाजपा के खाते में है। 2024 के चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव ने भी इस बात को लेकर बीजेपी पर तंज कसा था। उन्होंने कहा था, 'बिलासपुर 30 साल से नेतृत्व विहीन रहा, यहां के सांसद म्यूट सांसद बनकर काम करते रहे हैं।' बड़ी बात यह कि, इस बार मंत्री पद पहली बार जीतकर संसद पहुंचे तोखन साहू को मिला है। बिलासपुर लोकसभा का दायरा मुख्य रूप से दो जिले बिलासपुर और मुंगेली में आता है। कुछ हिस्सा गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले का भी है। राज्य निर्माण के बाद 2009 में बिलासपुर सीट का परिसीमन हुआ। इससे पहले अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट बिलासपुर में साल 1966 से लगातार पुन्नू लाल मोहले चार बार सांसद रहे।

सामान्य सीट बनने के बाद दिखा जूदेव/जोगी का मुकाबला

साल 2009 में जब परिसीमन हुआ, तब बिलासपुर लोकसभा को सामान्य सीट घोषित किया गया। इसके बाद जशपुर राजपरिवार के दिग्गज भाजपा नेता दिलीप सिंह जूदेव को भाजपा ने टिकट दिया। उनके सामने कांग्रेस ने महिला उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी कोटा विधायक रहीं डॉ. रेणु जोगी को प्रत्याशी बनाया। इस चुनाव में जूदेव को जीत हासिल हुई।

सीट बिलासपुर की, दबदबा मुंगेली का

राज्य बनने के बाद जितने भी लोकसभा चुनाव हुए उनमें बीजेपी ने मुंगेली जिले से ही अपना उम्मीदवार मैदान में उतारा है। 2009 में दिलीप सिंह जूदेव को छोड़कर 1991 के बाद हुए लोकसभा चुनाव में भाजपा ने अपना प्रत्याशी मुंगेली जिले से ही तय किया। इसमें 7 बार भाजपा चुनाव में जीत दर्ज कर चुकी है। चार बार लोकसभा चुनाव जीत कर मुंगेली जिले के भाजपा नेता पुन्नूलाल मोहले ने पार्टी की जमीन तैयार की। उनके पहले कांग्रेस के रेशमलाल जांगड़े, भाजपा के लखनलाल साहू और अरुण साव मुंगेली जिले के रहने वाले और चुनाव जितने वाले सांसद बने। इस बार भी भाजपा ने मुंगेली जिले के साहू समाज के नेता और पूर्व विधायक तोखन साहू जीत कर सांसद बने हैं।

मोदी सरकार में छग कोटे से एक मंत्री

साल 2014 में पहली बार देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद छत्तीसगढ़ से केवल एक ही सांसद को मौका मिला। उन्हें भी सीधे मंत्री बनाने के बजाए केंद्रीय राज्यमंत्री का ही दर्जा दिया गया। इनमें सीएम विष्णुदेव साय और रेणुका सिंह शामिल हैं। हालांकि कांग्रेस 2 में भी छत्तीसगढ़ से केवल चरणदास महंत को ही केंद्र में जगह मिली। राज्य बनने के पहले छत्तीसगढ़ से 2 मंत्री केंद्र में रहा करते थे। प्रदेश के डिप्टी सीएम अरुण साव भी मुंगेली जिले के रहने वाले हैं। वहीं सांसद निर्वाचित हुए तोखन साहू भी उसी जिले के लोरमी से हैं। उनके सहपाठी रघुवीर ₹ठाकुर बताते हैं कि उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई एक साथ की है। तब अरुण साव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी थे।

लोकसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत से बढ़ गई जिम्मेदारी : विष्णुदेव

'चूरमा बन गए बड़े-बड़े सूरमा'

देश में जहां इस साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा की सीटें घट गई हैं। वहीं छत्तीसगढ़ उन राज्यों में शामिल है, जहां बीजेपी ने अपनी सीट में इजाफा किया है। 11 में से 10 सीटों पर मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के बड़े-बड़े सूरमा को हमारे प्रत्याशियों ने चूरमा बना दिया।

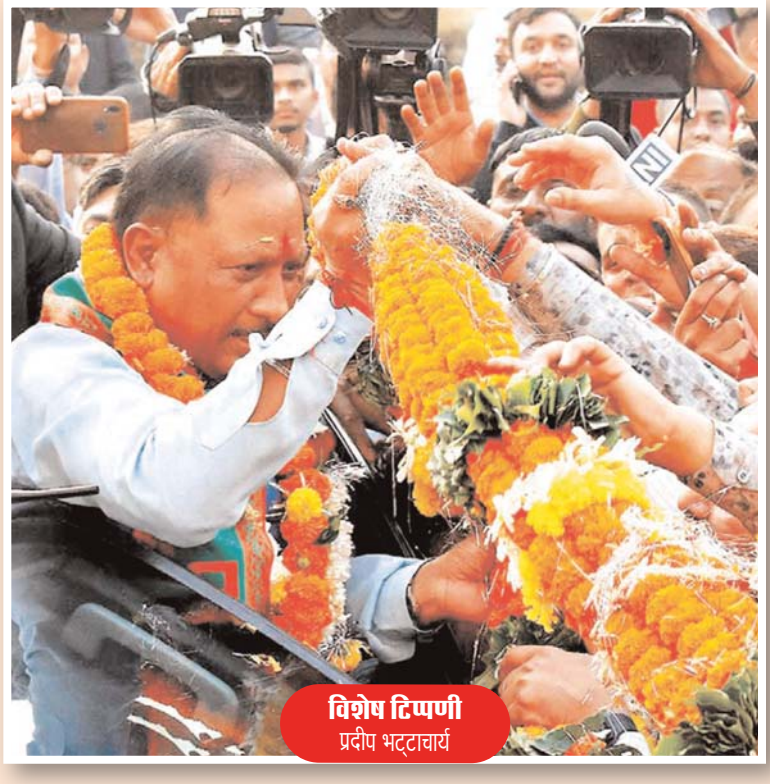

विशेष टिप्पणी
प्रदीप भट्टाचार्य

> प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को पटखनी देकर और चार-चार पूर्व मंत्रि यों को हराकर हमारे प्रत्याशी आए हैं। मैं सभी को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि चुनाव में जनता के आशीर्वाद से मिली ऐतिहासिक जीत के बाद जिम्मेदारी और बढ़ गई है। जिस पर हम सबको खरा उतरना है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें कही और छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता की मुहर है।

सी एम साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि तपती गर्मी में पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं सदस्यों के कठिन परिश्रम की बदौलत हमें ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा की जीत का श्रेय राज्य के मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्होंने कहा कि सबके अथक मेहनत से हमनें दोनों राज्यों में भाजपा का परचम लहराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने 54 सीटों के साथ 46 प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे और अब लोकसभा चुनाव में 6 प्रतिशत वोटों की वृद्धि हुई है, जिससे कि 68 विधानसभा सीटों में हमें जीत प्राप्त हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है और अब लोकसभा में जनता ने प्रचंड जीत दिलाकर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है।

प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में शामिल होने पहुंचे मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने उक्त बातें कही और छत्तीसगढ़ के सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को जीत की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में भाजपा को ऐतिहासिक जीत मिली और केंद्र में भी एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता की मुहर है।

सीएम साय ने भाजपा कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए कहा कि तपती गर्मी में पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन के पदाधिकारी, चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक एवं सदस्यों के कठिन परिश्रम की बदौलत हमें ऐतिहासिक परिणाम प्राप्त हुए हैं। इसके लिए सभी को बहुत-बहुत बधाई एवं धन्यवाद देता हूँ। पड़ोसी राज्य झारखंड और ओडिशा की जीत का श्रेय राज्य के मंत्रियों, भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को देते हुए उन्होंने कहा कि सबके अथक मेहनत से हमनें दोनों राज्यों में भाजपा का परचम लहराया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 में भाजपा ने 54 सीटों के साथ 46 प्रतिशत वोट प्राप्त किये थे और अब लोकसभा चुनाव में 6 प्रतिशत वोटों की वृद्धि हुई है, जिससे कि 68 विधानसभा सीटों में हमें जीत प्राप्त हुई है। इस पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में हमारी सरकार है और अब लोकसभा में जनता ने प्रचंड जीत दिलाकर बहुत बड़ी जिम्मेद री दी है। पड़ोसी राज्य ओडिशा और झारखंड में भाजपा की जीत पर उन्होंने कहा कि दोनों राज्यों में आयोजित जनसभा के दौरान मुझे मंच में आधे से

यह जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ की जनता की मुहर है।

ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ के नेताओं की मौजूदगी नजर आती थी। सबके प्रयासों से दोनों राज्यों में भाजपा इस मुकाम पर पहुंची है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि ओडिशा के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत के साथ हमारी सरकार बन रही है। राज्य में लोकसभा और विधानसभा के ऐतिहासिक जनादेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर मुहर लगायी है। वहां 25 साल सत्ता में रहे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को दोनों सीट में हराने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई है। जहाँ-जहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के नेता, मंत्री, कार्यकर्ता प्रचार के लिए गए थे वहां-वहां भारतीय जनता पार्टी को अच्छी सफलता मिली है। कांग्रेस के ज्यादातर प्रत्याशी 2018-23 के बीच मंत्री रहे, वे भी लोकसभा चुनाव में पराजित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित उनके साथ सरकार में मंत्री रहे अन्य लोग भी बुरी तरह पराजित हुए हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने एक्सीडेंटल जीत हासिल की थी जिसे प्रदेश की जनता ने 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हें सत्ता से बेद खल कर नकार दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें प्राप्त हुई हैं और अब 10 निदर्लीय सांसदों ने भी अपना समर्थन देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को मजबूत करने का काम किया है। कांग्रेस पार्टी एक समय 415 सीटों पर होती थी जो आज 99 सीटों में ही सिमटकर रह गई है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी में 6 प्रतिशत वोट प्राप्त किए थे जो आज बढ़कर 2024 में 36 प्रतिशत हो गया है और 56 प्रतिशत से ज्यादा वोट पाने वाली कांग्रेस पार्टी आज 21 प्रतिशत वोट पाकर सिमट गई है।

जन-जन तक पहुंचाएंगे योजनाएं : देव

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कहा कि जब छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव हुआ था तो उस समय के एक्जिट पोल में भाजपा को कम सीटें मिलती बताई जा रही थी, लेकिन प्रदेश की जनता ने भाजपा को अपना भरपूर समर्थन और आशीर्वाद देते हुए प्रदेश की 54 विधानसभा सीटों पर छत्तीसगढ़ में एक मजबूत सरकार बनाने का जनादेश दिया। देव ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार विधानसभा चुनाव के दौरान किए अपने सभी वादों को प्रदेश में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में तेजी के साथ पूरा कर रही है। अब हमें केंद्र एवं राज्य सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना है, ताकि सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी मिल सके।

विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे: जम्वाल

क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल ने चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा को अर्जित सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि आप सभी कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने चुनाव में जो अनथक परिश्रम किया है, यह सब उसी का प्रतिफल है। आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हम सब एक बार फिर देश में एनडीए की सरकार बनाने में सफल हुए हैं। जम्वाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराने के लिए देश विरोधी ताकतों ने तो जी-तोड़ कोशिशें खूब की लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं के परिश्रम के आगे वे ताकतें सफल नहीं हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर देश तेजी से विकास करेगा और एनडीए की मजबूत सरकार देश को विकसित बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी।

लक्ष्य से ज्यादा हासिल किया वोट: शर्मा

भाजपा चुनाव प्रबंधन समिति के प्रदेश संयोजक शिवरतन शर्मा ने चुनाव प्रबंधन समिति के सभी पदाधिकारियों व सदस्यों को लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता के लिए बधाई देते हुए कहा कि भाजपा ने चुनाव की सफलता के लिए 38 प्रकार की समितियाँ बनाई थीं और चुनाव में उन समितियों ने पूरे समर्पण के साथ काम करके प्रदेश की 11 में से 10 सीटों पर भाजपा की जीत सुनिश्चित की। शर्मा ने कहा कि केंद्रीय नेतृत्व द्वारा दिया गया लक्ष्य लोकसभा चुनाव में भाजपा ने प्राप्त किया है। हमें 51 प्रतिशत वोट पाने का लक्ष्य दिया गया था और आप सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से हमने छत्तीसगढ़ में 52.5 प्रतिशत वोट प्राप्त किया यानी कि विधानसभा चुनाव से 6 प्रतिशत ज्यादा वोट भाजपा को प्राप्त हुआ।

बाहरी 'गो बैक'

भारी पड़ा भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों पर 'बाहरी' होने का टैग

इस बार के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की 11 सीटों में करीब- करीब आधी सीटों पर बाहरी बनाम स्थानीय का मुद्दा रहा। कहीं जातीय समीकरण को देखते हुए तो कहीं सियासी कद को देखते हुए भाजपा और कांग्रेस ने प्रत्याशियों को एक से दूसरी जगह शिफ्ट किया। लेकिन ऐसे प्रत्याशियों पर 'बाहरी' होने का टैग लगाकर सामने वाली पार्टी ने अभियान छेड़ा । नतीजा ये हुआ कि ऐसे सभी प्रत्याशियों को शिकस्त देखनी पड़ी।

छत्तीसगढ़ में सत्ताधारी दल भाजपा को 11 में से जिस इकलौती सीट पर हार का सामना करना पड़ा, वो कोरबा लोकसभा की सीट है। यहां नेता प्रतिपक्ष डॉ. चरणदास महंत की पत्नी ज्योत्सना महंत ने दूसरी बार जीत दर्ज की है। 6 महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव में जीत-हार के समीकरण और वोट परसेंट को देखते हुए भाजपा पहले ही ये समझ गई थी कि कोरबा में फतह आसान नहीं। इसी लिए उसने दुर्ग जिले की कद्दावर नेता सरोज पांडेय को कोरबा से मैदान में उतारा। तब कांग्रेस ने ज्योत्सना महंत के नाम का ऐलान नहीं किया था। हालांकि ये पता था कि सीटिंग सांसद की टिकट कांग्रेस नहीं काटेगी और इसी रणनीति के तहत एक महिला के सामने महिला उम्मीदवार को मौका दिया गया। लेकिन चुनाव के शुरू होते ही कांग्रेस ने उसे बाहरी प्रत्याशी के रुप में प्रचारित किया। मार्च के पहले हफ्ते में उम्मीदवार घोषित होने के बाद जब सरोड पांडे कोरबा पहुंची थीं, तो उन्हें बाहरी होने को लेकर सवाल किया गया। तब उन्होंने कहा था कि बाहरी होने का सवाल ही नहीं है। क्योंकि जो वर्तमान सांसद यानी ज्योत्सना महंत हैं, वह भी कोरबा से नहीं हैं। उन्होंने कहा था कि चरण दास महंत खुद यहां नहीं रहते और मुझे बाहरी बताते हैं। मैं बाहर की हूं तो क्या सोनिया गांधी यहां की हैं? उनके इस जवाब पर भीड़ ने तालियां बजाकर उनका समर्थन किया। लेकिन ये तालियां वोटों में तब्दील नहीं हुईं। यहां बाहरी होने का आरोप सरोज पांडेय को भारी पड़ा और वे चुनाव हार गईं। दुर्ग की पूर्व सांसद सरोज पांडेय ने काफी अच्छा चुनाव लड़ा, लेकिन कोरबा की जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। कांग्रेस की ज्योत्सना महंत ने 43283 मतों से उन्हें हरा दिया। कोरबा में जो आरोप भाजपा प्रत्याशी को झेलना पड़ा, वैसे ही कांग्रेस को राजनांदगांव, जांजगीर चापां, महासमंदु और बिलासपुर में झेलना पड़ा।

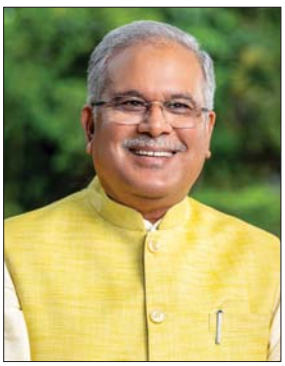

पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग जिले के पाटन इलाके से हैं। पाटन से वे वर्तमान में विधायक भी हैं। लेकिन पार्टी ने उन्हें दुर्ग लोकसभा की बजाय राजनांदगांव लोकसभा सीट से टिकट देकर मैदान में उतारा। भूपेश बघेल के नाम का ऐलान होते ही राजनांदगांव इलाके में भाजपा कार्यकर्ता उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताते हुए ढोल पीटने लगे। हर किसी को लग रहा था कि भूपेश बघेल मौजूदा सांसद संतोष पांडे पर भारी पड़ेंगे। लेकिन उन पर दुर्ग छोड़कर राजनांदगांव आने और बाहरी होने का ऐसा तमगा लगा कि वे प्रचार अभियान में बहुत आगे होते हुए भी मतदान में पिछड़ गए। उन्हें संतोष पांडेय ने बड़े अंतर से हरा दिया। कुछ यही जांजगीर-चांपा की सीट में शिव डहरिया के साथ हुआ। आरंग में रहने वाले शिव डहरिया जांजगीर-चांपा जाकर लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा ने उनके मुकाबले कमलेश जांगड़े को मैदान में उतारा था। सक्ती जिले के एक छोटे से गांव मसनिया खुर्द की सरपंच होने के बावजूद उन्होंने भूपेश बघेल की सरकार में कद्दावर मंत्री रहे शिव डहरिया को बड़े अंतर से शिकस्त दी। कुछ यही कहानी भूपेश सरकार में गृहमंत्री रहे ताम्रध्वज साहू की भी है। यहां उनके मुकाबले भाजपा की रुपकुमारी चौधरी मैदान में थी। अपना क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में मैदान संभालने वाले ताम्रध्वज साहू शुरू से ही बीजेपी के निशाने पर रहे। दुर्ग जिले की विधानसभा सीट से कांग्रेस के विधायक देवेंद्र यादव को भी पार्टी ने बिलासपुर में मैदान में उतार दिया। इसके पीछे कांग्रेस की रणनीति थी कि बिलासपुर में ओबीसी वर्ग के तोखन साहू भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां यादव बहुल होने का देवेंद्र यादव को फायदा मिल सकता है। इसीलिए पार्टी ने बाहरी प्रत्याशी को वहां से चुनाव लड़ने का रिस्क लिया। लेकिन उनका ये फैसला भारी पड़ गया। देवेंद्र यादव को शुरुआत से ही बिलासपुर में ही अपनी पार्टी के लोगों से विरोध का सामना करना पड़ा। मान-मनौवल के बाद समीकरण बना तो जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया।

छत्तीसगढ़ के सियासी इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब एक ही जिले दुर्ग के चार बड़े नेताओं को प्रदेश की चार अलग-अलग लोकसभा सीटों से मैदान में उतारा गया। कांग्रेस ने अपने 3 बड़े नेताओं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राजनांदगांव, पूर्व मंत्री ताम्रध्वज साहू को महासमुंद और विधायक देवेंद्र यादव को बिलासपुर सीट से प्रत्याशी बनाया गया था। लेकिन सभी जगहों पर सारे मुद्दे दरकिनार हो गए। सिर्फ एक ही मुद्दा चुनाव प्रचार के दौरान गूंजता रहा, कि प्रत्याशी बाहरी है और जनता ने उन्हें बाहरी प्रत्याशी बताते हुए नकार दिया। हालांकि ये प्रत्याशी प्रचार के दौरान और सभाओं में वादे और दावे करते रहे कि वे यहीं के होकर रहेंगे। उनके क्षेत्र का विकास करेंगे, लेकिन नतीजे बताते हैं कि जनता को उनकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजनांदगांव से भूपेश बघेल को भाजपा के संतोष पांडेय से 44411 वोटों से हरा दिया। महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को भाजपा की रूपकुमारी चौधरी ने 1 लाख 45 हजार 456 वोटों से हराया। वहीं बिलासपुर में देवेंद्र को भाजपा प्रत्याशी तोखन साहू ने 1 लाख 62 हजार 828 मतों से मात दी।

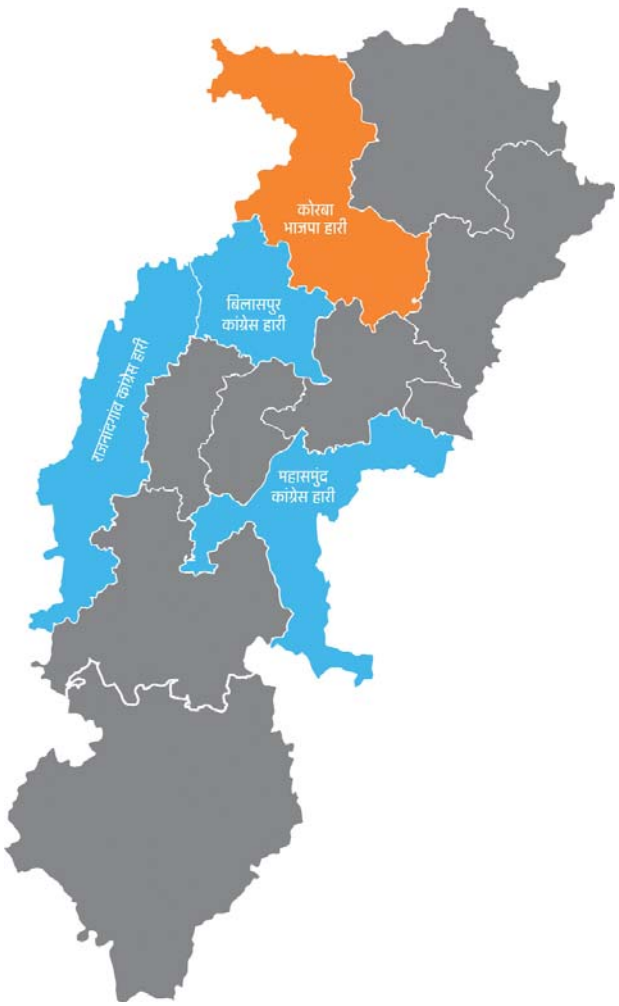

इसलिए फंस गए राजेंद्र साहू

दुर्ग जिले के सारे दिग्गज कांग्रेस नेता बाहर दूसरे जिलों की लोकसभा सीटों से चुनाव लड़ रहे थे। भूपेश बघेल के राजनांदगांव में फंसे होने, ताम्रध्वज साहू के महासमुंद में और देवेंद्र यादव के बिलासपुर में चुनाव लड़ने से दुर्ग लोकसभा सीट के प्रत्याशी राजेंद्र साहू बुरी तरह फंस गए। उन्हें पार्टी के दिग्गज नेताओं के समर्थन और प्रचार का पूरा मौका और फायदा नहीं मिला। तीनों ही प्रत्याशी अपने समर्थकों और कर्मठ कार्यकर्ताओं को लेकर अपनी उम्मीदवारी वाली लोकसभा सीट में चुनावी मोर्चे पर डट गए।

नहीं चला जाति पर जोर..

'जाति न पूछौ साधु की...' लेकिन कबीर की कही ये बात तब पूरी तरह खारिज हो जाती है, जब बात सियासत की हो। देश के हर सूबे में सारे सियासी बिसात सिर्फ जातियों को देककर ही बिछाए जाते हैं। ये अलग बात है कि वोटर्स जब अपने पर आता है, तो वो सियासी दलों के सारे समीकरण फेल करते हुए ऐसे नतीजे देता है कि सारी रणनीति धरी रह जाती है। इस बार भी छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों में जातिगत समीकरण, लोकसभा क्षेत्रों में किसी खास वर्ग की बहुलता को ध्यान में रखते हुए उम्मीदवार मैदान में उतारे गए। लेकिन कांग्रेस के फ्रेम में नतीजों को देखें तो जाति का जोर कहीं नहीं चला। हां, आंकड़ों के आइने में बीजेपी कह सकती है कि उसे फायदा हुआ है।

हर चुनाव में सारे सियासी समीकरण जातियों को देखकर ही तय किए जाते हैं। इस बार भी छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर जातिगत समीकरण को ध्यान में रखते हुए भाजपा और कांग्रेस चुनाव से छह महीने पहले से रणनीति बना रहे थे। इसी आधार पर दोनों दलों ने अपने-अपने उम्मीदवारों को टिकट दी थी। लेकिन चुनाव नतीजों ने साबित किया कि जातिगत समीकरण का दांव फेल हो गया है, खासतौर से कांग्रेस के लिए। लोकसभा की 11 सीटों में चुनावी रणनीति की बिसात जातिगत आधार पर बिछाई गई थी। 4 सीटों पर मुकाबला आदिवासी बनाम आदिवासी का था। वहीं 3 सीटों पर ओबीसी कैं डिडेट आमने-सामने थे। जबकि जांज गीर लोकसभा की सीट पर एससी बनाम एससी और एक सीट पर सामान्य का मुकाबला सामान्य से था। वहीं 2 सीटों पर ओबीसी का मुकाबला सामान्य उम्मीदवार कर रहे थे। कांग्रेस के लिए जातिगत समीकरण पूरी तरह फेल रहा और उन्हें 11 में से सिर्फ एक सीट पर ही सफलता मिली। वहीं ये कह सकते हैं कि भाजपा के लिए सारे दांव अच्छे रहे। ओबीसी, आदिवासी वोटर्स के कॉकटेल वाली सीट कोरबा लोकसभा से कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार ज्योत्सना महंत को मौका दिया।

वहीं भाजपा ने दुर्ग जिले की दिग्गज भाजपा नेत्री सरोज पांडेय के मैदान में उतारा। 11 में से यही वो इकलौती सीट है, जहां से भाजपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा प्रदेश की 10 अन्य सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। उसकी तमाम रणनीति और सियासी बिसात काम कर गई। रायपुर लोकसभा सीट पर भाजपा के बृजमोहन अग्रवाल के सामने कांग्रेस के विकास उपाध्याय थे। जातिगत समीकरण के आधार पर न यहां टिकट बांटा गया और न ही रणनीति बनी। यहां मुकाबला साख का था। जिसे उम्मीद के मुताबिक बीजेपी ने फतह किया। राजनांदगांव ओबीसी सीट है। इसके साथ ही यहां 24 फीसदी एसटी तो लगभग 11 फीसदी एससी वोट हैं। बावजूद लोकसभा में जातिगत समीकरण की कुछ खास भूमिका नहीं रही। क्योंकि इसका इतिहास ही ऐसा है। ओबीसी वोटर्स की बहुलता को देखते हुए कांग्रेस ने ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे के रुप में भूपेश बघेल को मैदान में उतारा। लेकिन यहां बीजेपी के संतोष पांडेय के सामने पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस के सबसे बड़े नेता भूपेश बघेल चुनाव हार गए। बिलासपुर लोकसभा की सीट पर भाजपा ने तोखन साहू तो कांग्रेस ने विधायक देवेंद्र यादव को मौका दिया।

छत्तीसगढ़ ही नहीं दूसरे राज्यों में भी चला मुख्यमंत्री साय का जादू

सुपर स्ट्राइकर सीएम

लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों के करीब-करीब हर दूसरे विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने चुनावी सभा और रैली की। यही नहीं, तीन चरणों में छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर चुनाव हो गए, तो उन्होंने पड़ोसी राज्यों मध्यप्रदेश, ओडिशा और झारखंड में भी पार्टी के लिए जमकर मेहनत की। छत्तीसगढ़ में तो 11 में से 10 सीटें भाजपा जीत ही गई, पड़ोसी राज्यों में भी उनका जादू नजर आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लोकसभा चुनाव के दौरान जहां-जहां चुनाव प्रचार करने गए वहां लगभग सभी सीटों पर पार्टी प्रत्याशी की जीत हुई है।

देश में हुए लोकसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। छत्तीसगढ़ में 10 सीटों सहित पूरे देश में भाजपा नीत एनडीए गठबंधन ने 293 सीटों पर जीत हासिल की है। इसके साथ ओडिशा विधानसभा चुनाव में पहली बार भाजपा ने बहुमत हासिल किया है, तो दूसरी ओर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत हासिल हुई है। छत्तीसगढ़ सहित मध्यप्रदेश और ओडिशा में भाजपा की प्रचंड जीत में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का अहम योगदान रहा। उन्होंने जहाँ-जहाँ सभाएं की वहां अधिकतर जगहों में भाजपा का परचम लहराया। साय का छत्तीसगढ़ में 91 प्रतिशत, मध्यप्रदेश में 100 प्रतिशत और ओडिशा में 86 प्रतिशत सक्सेस स्ट्राइक रेट रहा। इसलिए लोग अब विष्णु देव साय को सुपर स्ट्राइकर सीएम की संज्ञा दे रहे हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं का सूत्र वाक्य अंगीकार कर चुनावी महासमर में सफलता के नए आयाम तक पहुंचने वाले सीएम साय इसका श्रेय संगठन के कार्यकर्ताओं और जनता को देते हैं। उनका कहना है कि भीषण गर्मी की परवाह न कर कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की। संगठन के हर नेता ने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया, जिसका नतीजा सामने है। वह यह नहीं बताते कि पूरे चुनावी यात्रा में उसी भीषण गर्मी से उन्हें भी दो-चार होना पड़ा। अपनी मेहनत पर उन्हें चर्चा पसंद नहीं वे इसे अपना कर्तव्य मानते हैं। जनता से मिले आशीर्वाद को सिर झुका कर स्वीकार करने वाले सीएम साय की यही नम्रता और सरलता उनके सियासी कद को बड़ा बनाती है।

11 सीटों के लिए 64 सभाएं और रोड शो

छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों में साय ने कुल 64 जनसभाएं एवं रोड शो की। जहाँ उन्होंने बस्तर लोकसभा में 7 जनसभा और रोड शो किया। दूसरे चरण के अंतर्गत कांकेर, राजनांदगांव और महासमुंद में कुल 15 जनसभाएं की। इन चारों लोकसभा सीटों में भाजपा ने जीत दर्ज की। तीसरे चरण की बची हुई 7 सीटों रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, सरगुजा और कोरबा में सीएम साय ने कुल 42 जनसभाएं की। जिसमें कोरबा लोकसभा में मामूली अंतर से हुई हार को छोड़ दें तो ग्यारह में से 10 सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की और अपना परचम लहराया। अगर इसका विनिंग प्रतिशत निकालें तो मुख्यमंत्री साय की सभाओं का सक्सेस रेट 91 प्रतिशत रहा। मतलब सीएम साय सुपर स्ट्राइकर साबित हुए और अपने तूफानी दौरों की बदौलत से कांग्रेस के पसीने छुड़ा दिए। अपनी हर सभा में कांग्रेस को सबक सिखाने की बात करने वाले सीएम साय ने कांग्रेस को गहरा सबक सिखाया।

संगठनात्मक अनुभवों का मिला लाभ

लोकसभा चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी सीएम साय को छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने के साथ-साथ प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष के तौर पर सीएम साय के संगठनात्मक अनुभवों का लाभ लेने में भी सफल रही। पंच से मुख्यमंत्री पद तक की यात्रा के दौरान सीएम साय ने अनेक राजनैतिक जमीनी अनुभव प्राप्त किए हैं। वे रायगढ़ क्षेत्र से लगातार चार बार सांसद और केन्द्रीय राज्य मंत्री भी रह चुके है। उनके व्यापक प्रभाव क्षेत्र का लाभ भाजपा को मिला है। सीएम साय छत्तीसगढ़ के जशपुर क्षेत्र के निवासी है। यह क्षेत्र ओडिशा तथा झारखंड से सटा हुआ है। मध्यप्रदेश से भी इस क्षेत्र की निकटता है। इस तरह इस पूरे क्षेत्र की संस्कृति और राजनीतिक परिस्थितियों की सीएम साय को गहरी समझ है। तेलंगाना का भद्राचलम क्षेत्र छत्तीसगढ़ के कोण्टा और सुकमा जिलों से सटा हुआ है। इस पूरे क्षेत्र की आदिवासी संस्कृ ति और मुद्दे एक जैसे हैं। यह पूरा क्षेत्र नक्सलवाद से पीड़ित है तथा दोनों राज्यों के बीच सड़क एवं संचार कनेक्टिविटी की मांग क्षेत्र के लोग लंबे समय से करते रहे हैं।

लोकसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ तथा सीमावर्ती राज्यों में चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को महती जिम्मेदारी देने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रंग लाई। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी को हासिल कुल जमा सीटों में बड़ा हिस्सा उन क्षेत्रों का नजर आ रहा है, जहां पर साय ने सघन रूप से प्रचार किया। मध्य भारत के वरिष्ठ आदिवासी नेता के रूप में सीएम साय की लोकप्रिय छवि का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, ओडिशा, झारखंड, तेलंगाना, में करीब तीन महीनों तक लगातार चुनाव प्रचार किया। ये सभी आदिवासी क्षेत्र है तथा इन क्षेत्रों के मुद्दे एक जैसे है। अपनी चुनावी सभाओं के माध्यम से सीएम साय मतदाताओं को यह समझाने में कामयाब रहे कि आदिवासी मुद्दों का समाधान केवल भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। वें यह भी समझाने में सफल रहे कि जिस तरह एक आदिवासी को छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बनाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आदिवासी हितों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता साबित की है, उसी तरह सभी आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण के लिए उनकी गारंटियों पर भरोसा किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी ने कुल 240 सीटें हासिल की है, जबकि मध्य भारत के आदिवासी क्षेत्रों में पार्टी को 75 सीटें प्राप्त हुई है। सीएम साय ने चुनाव की घोषणा होने से बहुत पहले ही इस सभी क्षेत्रों में चुनाव प्रचार शुरू कर दिया था। इस दौरान उन्होंने 109 जन सभाएं और 17 रोड-शो किए। छत्तीसगढ़ में शुरूआती तीन चरणों में ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सीएम साय ने स्वयं को पड़ोसी राज्यों में चल रहे चुनाव प्रचार में पूरी तरह झोंक दिया। नौतपे की कड़ी धूप के दौरान भी उनका हेलीकॉप्टर लगभग हर रोज चुनावी आसमान पर उड़ान भरता रहा। सीएम साय को जिन राज्यों में चुनाव प्रचार की जिम्मेद ारी सौपी गई थी, उनमें भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में क्लिन स्वीप किया है। छत्तीसगढ़ की 11 में से 10 सीटों और मध्यप्रदेश की 29 में से 29 सीटों में विजय हासिल कर पार्टी ने कांग्रेस का पूरी तरह सूपड़ा साफ कर दिया। ओडिशा में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 24 सालों से सत्ता पर काबिज नवीन पटनायक की सरकार को दर किनार कर विधानसभा चुनाव में पहली बार सत्ता हासिल करने में कामयाबी हासिल की है। लोक सभा में पार्टी ने ओडिशा में 20 सीटें हासिल की है। झारखंड में भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन करते हुए 8 सीटें हासिल की है। तेलंगाना में इस बार भाजपा की सीटों की संख्या दोगुनी हो गई है। पार्टी ने वहां 8 सीटें प्राप्त की है। सीएम साय ने इन सभी राज्यों के सीमावर्ती क्षेत्रों के साथ-साथ अंदरूनी क्षेत्रों में भी प्रचार किया। मध्यप्रदेश में सिंगरौली, सीधी, शहडोल, मंडला, डिंडौरी, कटनी, पन्ना, ओडिशा में झारसुगुड़ा, कोटपाड़, हटबरौंदी, उमरकोट, लक्ष्मीपुर, कोंटांगी, कोरापुट, कालाहाडी, नुआपाड़ा, बिजेपुर, सुबड़पुर, बीरमित्रपुर, संदु रगढ़, कु चिंदा, झारखंड में पश्चिम सिंहभूम, सिमडेंगा, गुमला, जमशेदपुर, साहिबगंज , पाकुड़, दुमका में श्री साय ने धुआंधार चुनाव प्रचार किया।

ओडिशा में जीत से बढ़ा सियासी कद

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ओडिशा में भी जमकर पसीना बहाया। यहाँ सात लोकसभा सीटों में उन्होंने तूफानी जनसभाएं ली और भाजपा को 6 लोकसभा सीट बरगढ़, बलांगीर, कालाहांडी, नबरंगपुर, संबलपुर और सुंदरगढ़ सीटें जिताकर दी। विधानसभा स्तर पर भी यदि देखें तो यहां झारसुगुड़ा, कोटपाड़, उमरकोट, कोरापुट, तलसरा, बीजेपुर, बीरमहाराजपुर और कुचिंदा सीट को मिलाकर कुल आठ विधायक भी जिताने में वो कामयाब रहे। यहां लोकसभा चुनाव में उनका सक्सेस स्ट्राइक रेट 86 प्रतिशत रहा। बता दें कि ओडिशा की अपनी हर जनसभा में साय वहां की बीजेडी सरकार और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुखर रहे। उन्होंने ओडिशा की जनता को भाजपा द्वारा दी गई गारंटियों को बड़े ही विस्तार से बताया।

एमपी में 100 फीसदी सक्सेस रेट

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पड़ोसी राज्य मध्यप्रदेश में भी 8 जनसभाएं की। जिसमें कुल चार लोकसभा सीट खजुराहो, शहडोल, मंडला, सीधी में उन्होंने मोर्चा संभाला। इन चारों सीटों पर भी भाजपा ने बम्पर मतों से जीत हासिल की है। इसमें मुख्यमंत्री की सभाओं का सक्सेस रेट देखें तो पूरे सौ प्रतिशत का सक्सेस रेट है। विष्णु ने जिम्मेदारियों का किया निष्ठा पूर्वक निर्वहन केंद्रीय भाजपा द्वारा मिली जिम्मेदारियों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए विष्णु देव साय छत्तीसगढ़, ओडिशा और मध्यप्रदेश में भाजपा की प्रचंड जीत में अहम किरदार साबित हुए और मोदी जी की रणनीति को सफल बनाने में कामयाब हुए। इससे उनके सियासी कद में वृद्धि हुई, इसमें कोई संदेह नहीं है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव के नेतृत्व में सुशासन के ट्रैक पर छत्तीसगढ़ ने फिर से विकास की रफ्तार पकड़ ली है। बीते छह माह पर नजर डाले तो साय सरकार ने किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए बहुत कम समय में ऐतिहासिक फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए वर्ष 2047 तक विकसित-छत्तीसगढ़ का निर्माण के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए विजन डाक्यूमेंट तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है।

विष्णुदेव सरकार ने डेढ़ दर्जन से अधिक फैसले किए

छह महीने : कई बड़े फैसले

खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना

विधानसभा चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ के लोगों को गारंटी दी थी कि छत्तीसगढ़ में लोगों के जीवन में खुशहाली और समृद्धि के लिए सुशासन की स्थापना की जाएगी। इसे ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक अलग सुशासन और अभिसरण विभाग का गठन किया है। यह विभाग कल्याणकारी नीतियों के सफल क्रियान्वयन, उपलब्ध संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग और जन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए काम कर रहा है। सभी विभागों को सुशासन के लिए अधिक से अधिक आईटी का इस्तेमाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्व. अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर 2023, सुशासन दिवस पर अटल मॉनिटरिंग पोर्टल का शुभारंभ किया गया है। साय सरकार ने आवासहीन और जरूरतमंद 18 लाख परिवारों के लिए प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति, 13 लाख से अधिक किसानों को धान की बोनस राशि, 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी, महतारी वंदन योजना में 70 लाख से अधिक गरीब परिवारों की महिलाओं को हर

माह एक-एक हजार रूपए देने जैसे अनेक निर्णयों पर क्रियान्वयन किया है। राज्य के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में माओवाद उन्मूलन के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियद नेल्लानार योजना शुरू की गई है। महतारी वंदन योजना, कृषक उन्नति योजना, रामलला दर्शन योजना, उद्यम क्रांति योजना जैसी कई अभिनव योजनाओं की शुरूआत हुई है। लोकतंत्र सेनानियों (मीसा बंदियों) की सम्मान निधि फिर से शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार

जरूरतमंद परिवारों को 18 लाख आवास

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सरकार बनने के दूसरे ही दिन कैबिनेट की बैठक आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी की गारंटी के अनुरूप 18 लाख 12 हजार 743 जरूरतमंद परिवारों को प्रधानमंत्री आवास उपलब्ध कराने स्वीकृति दे दी। इसके लिए 12 हजार 168 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है।

13 लाख किसानों को धान का बोनस

पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश के किसानों को गारंटी दी थी कि सरकार बनने पर राज्य के किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस, सुशासन दिवस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए का बकाया धान बोनस अंतरित कर इस गारंटी को भी पूरा किया है।

3100 में प्रति क्विंटल धान की खरीदी

सरकार ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ के समर्थन मूल्य की राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया। फिर 12 जनवरी को 24 लाख 75 हजार किसानों को अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ की राशि अंतरित की है।

70 लाख महिलाओं का वंदन

महतारी वंदन योजना के अंतर्गत महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरण का शुभारंभ प्रधानमंत्री की वर्चुअल उपस्थिति में 10 मार्च 2024 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह एक-एक हजार रुपए की सहायता राशि दी जा रही है। योजना का लाभ 70 लाख से अधिक महिलाओं को मिल रहा है।

शहीद वीर नारायण सिंह स्वास्थ्य योजना

राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के साथ ही शहीद वीरनारायण सिंह स्वास्थ्य योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है। राज्य के दो बड़े मेडिकल कॉलेज व अस्पतालों में भवन के विस्तार और सुविधाओं के विकास का काम शुरू कर दिया गया है।

कोरबा-बिलासपुर में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर

राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाइन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः प्रारंभ की गई है। इससे राज्य को मिलने वाले राजस्व में वृद्धि होगी।

श्री रामलला दर्शन योजना की शुरूआत

श्रद्धालुओं को अयोध्या में विराजमान श्री रामलला के दर्शन हेतु निःशुल्क आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य में श्री रामलला अयोध्या धाम दर्शन योजना संचालित की जा रही है। शासकीय व्यय में अब तक हजारों दर्शनार्थी श्री रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या भेजे जा चुके हैं।

तेन्दूपत्ता संग्रहण दर अब 5500 रूपए

राज्य में तेंदूपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 4000 रुपए प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर अब 5500 रुपए प्रति मानक बोरा कर दी गई है। चालू तेंदूपत्ता सीजन से ही 12 लाख 50 हजार तेंदूपत्ता संग्राहकों को योजना का लाभ मिल रहा है। संग्राहकों के लिए राज्य सरकार द्वारा चरण पादुका योजना भी शुरू की जाएगी।

भर्ती में युवाओं को पांच वर्ष की छूट

युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य सरकार ने अहम निर्णय लेते हुए पुलिस विभाग सहित विभिन्न शासकीय भर्तियों में युवाओं को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट का निर्णय लिया है। अभ्यर्थियों को 31 दिसंबर 2028 तक आयु सीमा में 05 वर्ष छूट का लाभ मिलेगा।

यूपीएससी की तर्ज पर होगी पीएससी

यूपीएससी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ पीएससी परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए यूपीएससी के पूर्व चेयरमेन प्रदीप कुमार जोशी की अध्यक्षता में आयोग का गठन कर दिया गया है। पीएससी की घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है।

पांच शक्तिपीठों का होगा विकास

शक्तिपीठों के विकास के लिए चारधाम की तर्ज पर 1000 किलोमीटर की परियोजना शुरू की जाएगी। ग्रामीण घरों को नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत 4500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

युवाओं के लिए उद्यम क्रांति योजना

राज्य में युवा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए उद्यम क्रांति योजना शुरू करते हुए बजट प्रावधान भी कर दिया है। इस योजना के तहत युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी पर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराए जाने की व्यवस्था की गई है।

अधोसंरचना और कनेक्टीविटी पर जोर

राज्य में सड़क, रेल और हवाई यातायात की सुविधाओं के विस्तार का काम भी शुरू हो चुका है। जशपुर और बलरामपुर हवाई पट्टी के विस्तार के लिए बजट में प्रावधान कर दिया गया है। अंबिकापुर और जगदलपुर हवाई अड्डों में भी सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

गरीबों के लिए मुफ्त राशन

छत्तीसगढ़ सरकार ने 68 लाख गरीब परिवारों को 05 साल तक मुफ्त राशन देने का निर्णय लिया है। इसके लिए बजट में 34 सौ करोड़ रुपए का प्रावधान है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के अंतर्गत प्रति वर्ष 10 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

राजिम कुम्भ कल्प की पुनः शुरूआत

राज्य की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन के लिए राजिम मेले का आयोजन पुनः उसके व्यापक स्वरूप में राजिम कुंभ कल्प के रूप में शुरू कर दिया गया है। बस्तर में प्राचीन काल से चले आ रहे अनेक ऐतिहासिक मेलों को भी शासकीय संरक्षण और सहायता दी जा रही है।

दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है। भूमि संबंधी विवादों और दिक्कतों को दूर करने के लिए भू-नक्शों की जियो रिफरेंसिंग पर भी रणनीति तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय बीते 13 जून से सभी विभागों में प्रशासनिक कसावट लाने के लिए समीक्षा बैठक लेने का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि जन कल्याणकारी कार्यक्रम का क्रियान्वयन, पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता रखें। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा है कि आम नागरिकों की दिक्कतें दूर करने के लिए संवेदनशील होकर कार्य करें। लोकसभा निर्वाचन के बाद अब शासन की योजनाओं को आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार तेजी से काम कर रही है। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना जैसी अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन पर तैयारी शुरू कर दी गई है। राजस्व प्रशासन को भी मजबूत किया जा रहा है।

देश की जीडीपी में कृषि का बड़ा योगदान

विष्णु सरकार की सुध से खेती किसानी को नया सम्बल

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, इससे राज्य में खेती-किसानी को नया सम्बल मिला है।

छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार भी कृषि ही है और यह धान का कटोरा कहलाता है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अल्पावधि में राज्य के किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं, इससे राज्य में खेती-किसानी को नया सम्बल मिला है। किसान बेहद खुश है। उनके मन में एक नई उम्मीद जगी है।

छत्तीसगढ़ की नई सरकार ने प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की समर्थन मूल्य पर खरीदी तथा दो साल के बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रूपए का भुगतान करके एक ओर जहां अपना संकल्प पूरा किया है, वहीं दूसरी ओर किसानों से बीते खरीफ विपणन वर्ष में 144.92 लाख मेट्रिक टन धान की रिकार्ड खरीदी की है। किसानों को समर्थन मूल्य के रूप में 31,914 करोड़ रूपए का भुगतान एवं किसान समृद्धि योजना के माध्यम से मूल्य की अंतर की राशि 13,320 करोड़ का भुगतान करके यह बता दिया है कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली और अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का रास्ता खेती-किसानी से ही निकलेगा।

किसानों का मानना है कि राज्य सरकार के अब तक के फैसलों से यह स्पष्ट हो गया है कि यह सरकार किसानों की हितैषी है। खेती-किसानी ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार है। कृषि के क्षेत्र में सम्पन्नता से ही छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी और विकसित राज्य बनाने का सपना साकार होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने इस साल कृषि के बजट में 33 प्रतिशत की वृद्धि की है।

खरीफ सीजन 2024-25 के लिए राज्य में 13.68 लाख मैट्रिक टन उर्वरकों की मांग के विरूद्ध अब तक 9.13 लाख मैट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित कर ली गयी है, जो मांग का 67 प्रतिशत है। सोसायटियों में विभिन्न खरीफ फसलों के बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। खरीफ सीजन 2024-25 में 5 लाख 59 हजार 203 क्विंटल बीज की मांग के विरूद्ध 6 लाख 39 हजार 4 क्विंटल बीज उपलब्ध है, जो कि मांग का 114 प्रतिशत है।

2023 के चुनाव में रिकार्ड मतों से दर्ज की जीत

सरकार ने अपने संकल्प के मुताबिक समर्थन मूल्य पर खरीदे गए धान में प्रति क्विंटल 917 रूपए के मान से अंतर की राशि भी दे दी है। किसानों को प्रति क्विंटल के मान से 3100 रूपए के भुगतान की यह राशि देश में सर्वाधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस साल के बजट में कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10 हजार करोड़ की व्यवस्था की गई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में कृषि को बढ़ावा देने के लिए कई अभिनव पहल की जा रही है। जशपुर जिले के कुनकुरी में कृषि व्यवसाय प्रबंधन महाविद्यालय एवं अनुसंधान केन्द्र तथा बलरामपुर जिले के रामचंद्रपुर में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एवं प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी महाविद्यालय खोलने की व्यवस्था बजट में की है।

समझे...रायपुर लोस बनाम विस सीटों का गठित

कृषि में आधुनिक उपकरणों के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय की स्थापना एवं राज्य स्तरीय नवीन कृषि यंत्र परीक्षण प्रयोगशाला के भवन का निर्माण, दुर्ग एवं सरगुजा जिले में कृषि यंत्री कार्यालय तथा रासायनिक उर्वरकों की जांच के लिए सरगुजा जिले में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाएगी। राज्य के किसानों को सहकारी एवं ग्रामीण बैंकों से ब्याज मुक्त कृषि ऋण उपलब्ध कराने के लिए 8 हजार 500 करोड़ का लक्ष्य तथा भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहायता हेतु दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना के तहत भूमिहीन परिवारों को प्रतिवर्ष 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता देने के लिए बजट में 500 करोड़ रुपए का प्रावधान है।

किसानों पर राज्य सरकार का फोकस

छत्तीसगढ़ में किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, सौर सुजला योजना के माध्यम से सिंचित रकबे में बढ़ोत्तरी का प्रयास किया जा रहा है। नवीन सिंचाई योजना के लिए 300 करोड़ रूपए, लघु सिंचाई की चालू परियोजनाओं के लिए 692 करोड़ रूपए, नाबार्ड पोषित सिंचाई परियोजनाओं के लिए 433 करोड़ रूपए एवं एनीकट तथा स्टाप डेम निर्माण के लिए 262 करोड़ रूपए का बजट प्रावधान छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। छत्तीसगढ़ में किसानों एवं भूमिहीन मजदूरों की स्थिति में सुधार, कृषि एवं सहायक गतिविधियां के लिए समन्वित प्रयास पर राज्य सरकार का फोकस है।

खाद-बीज को लेकर नहीं होनी चाहिए दिक्कत

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने वर्तमान खरीफ सीजन को देखते हुए राज्यभर की सहकारी समितियों में सोसायटियों में गुणवत्तापूर्ण खाद-बीज भंडारण एवं उठाव की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसानों को खाद-बीज के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसलिए पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपने खेती-किसानी के दीर्घ अनुभव के आधार पर कहा है कि खरीफ सीजन में किसान भाईयों द्वारा डी.ए.पी. खाद की मांग ज्यादा की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए डी.ए.पी. खाद की मांग और सप्लाई पर विशेष निगरानी रखी जानी चाहिए।

छत्तीसगढ़ में उम्मीदों की नई रोशनी फैलाने में सफल

विष्णु देव सरकार को मुख्यमंत्री बने छह माह जरूर हो चुके हैं लेकिन निर्णय, योजनाओं का क्रियान्वयन, भावी रणनीति को मूर्तरूप देने के लिए उन्हें 4 माह का ही समय मिला है।

लोकतंत्र में जहां जनता अपने नेतृत्व को वायदे पूरे करने के लिए पांच साल का जनादेश प्रदान करती है। ऐसे में किसी प्रदेश के मुखिया से महज छह माह के समय में इन वायदों को पूरा करने की आशा आमतौर पर बेमानी होती है। लेकिन मन में जज्बा, कुछ करने की लालसा, संवेदनशील प्रयास और समन्वित रणनीति के तहत कार्य किया जाए तो छह माह में भी इतिहास गढ़ा जा सकता है। महज छह माह में किसी भी सरकार के कामकाज का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता इसके बावजूद विष्णु देव साय सरकार जिस तेजी के साथ काम को आगे बढ़ा रही है, निश्चित ही यह एक मिसाल है।

प्रदेश में एक अलग छाप छोड़ने में हुए सफल

मुख्यमंत्री श्री साय ने विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए अधिकांश वायदों को पूरा करने के लिए जरा भी वक्त जाया नहीं किया। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है। शपथ ग्रहण 13 दिसम्बर 2023 के बाद 15 अप्रैल 2024 यानी 4 माह 02 दिन। 16 मार्च 2024 से 6 जून 2024 यानी 2 माह 21 दिन लोकसभा निर्वाचन की वजह से आदर्श आचार संहिता पूरे प्रदेश में प्रभावशील रही। ऐसे में विष्णु देव सरकार को मुख्यमंत्री बने छह माह जरूर हो चुके हैं लेकिन निर्णय, योजनाओं का क्रियान्वयन, भावी रणनीति को मूर्तरूप देने के लिए उन्हें 4 माह का ही समय मिला है। मुख्यमंत्री श्री साय ने इन सब के बावजूद अपने सटीक निर्णयों से प्रदेश में एक अलग छाप छोड़ने में सफल हुए हैं। जब हम आधी आबादी की बात करते हैं तब उनकी स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वावलम्बन और सशक्तीकरण के लिए ठोस व दूरगामी रणनीति बनानी पड़ती है।

प्रदेश के 70 लाख विवाहित महिलाओं के जीवन में एक नई उम्मीद की किरण महतारी वन्दन योजना से मिली है। ईब से इंद्रावती तक यानी प्रदेश के चारों तरफ विवाहित महिलाओं को हर माह एक हजार रूपए दिए जा रहे हैं और इस तरह चार किश्ते दी जा चुकी हैं। राज्य सरकार द्वारा विवाहित माताओं-बहनों के खाते में राशि देने के पीछे आर्थिक सशक्तीकरण करना, उनके आर्थिक हालात को बेहतर करना प्रमुख उद्देश्य है।

दावे और वादे के पक्के मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रदेश के लाखों किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदने की गारंटी को पूरा करते हुए 32 हजार करोड़ रुपए के समर्थन मूल्य की राशि का भुगतान किसानों के खाते में किया गया, वहीं 24 लाख 75 हजार किसानों को कृषक उन्नति योजना के तहत अंतर की राशि 13 हजार 320 करोड़ रुपए अन्तरित की गई। खरीफ सीजन में रिकॉर्ड 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके अलावा किसानों को दो साल के धान के बकाया बोनस राशि 3 हजार 716 करोड़ रुपए देने जैसे साहसिक निर्णय लिए है। मुख्यमंत्री श्री साय संवेदनशील सरकार और किसानों के सरकार के रूप में महज छह माह में ही पहचान बनाने में सफल हुए। आदिवासियों की पीड़ा, संघर्ष, सम्मान और जरूरत को उनसे बेहतर कौन समझ पाएगा! सरकार बनाते ही तेन्दूपत्ता प्रति मानक बोरा 5 हजार 500 रूपए की गई, जिससे 12 लाख 50 हजार से अधिक तेंदूपत्ता संग्राहकों को लाभ मिल रहा है। कौन नहीं चाहता कि घर के बुजुर्ग तीर्थ यात्रा करें लेकिन आर्थिक अभाव, सुरक्षा और मार्गदर्शन आड़े आते हैं। ऐसे में विष्णु सरकार की मानवीय पहल यानी रामलला मंदिर दर्शन योजना से मन की मुराद पूरी हो रही है। कोई न सोए भूखे पेट, इस तरह के विचार को अपनी कार्य योजना में शामिल करें तो वह निश्चित ही मानवीय संवेदना ही है प्रदेश के 68 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पांच वर्षों तक मुफ्त अनाज देने जैसे निर्णय साबित कर रहे हैं कि सरकार गरीबों के कल्याण को प्राथमिकता दे रही है। खुद का घर, पक्का मकान यह सब सुनने में एक गरीब परिवार के लिए दिन में देखने वाले स्वप्न की तरह होता है। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए, 18 लाख प्रधानमंत्री आवास योजना के निर्माण की दिशा में प्रदेश जोरशोर से आगे बढ़ चुका है। ऐसे में गरीब के सिर में पक्का छत होना यानी सशक्त परिवार और खुशहाल समाज का प्रतीक बनेगा। सरकार में आते ही युवाओं की तकलीफ को समझा और पीएससी परीक्षा घोटाले को लेकर युवाओं के गुस्से और हताशा को समझते हुए मुख्यमंत्री श्री साय ने सीबीआई जांच की अनुशंसा की। शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देने से युवाओं के मन में खुशियां देखने को मिली है। जिस बस्तर अंचल की पहचान सुंदर प्राकृतिक परिवेश और अकूत संसाधनों से है तथा यहां के भोलेभाले आदिवासियों की कला संस्कृति ने देश और दुनिया को अपनी ओर खींचा है। इस स्वर्ग को दूषित करने का काम कुछ माओवादी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री साय के अडिग निर्णय, बेहतर रणनीति का ही परिणाम है कि महज छह माह में 129 माओवादियों को सुरक्षा बलों के जवानों ने ढेर किया है, 488 गिरफ्तार हुए हैं 431 आत्मसमर्पण किया और इस तरह बस्तर की उम्मीद की नई रौशनी देखने को मिलने लगी है।

बृजमोहन अग्रवाल ने छोड़ा मंत्री पद

भावुक होकर बोले : किसी को कष्ट हुआ हो तो माफ करे, सीएम को सौंपा इस्तीफा

बृजमोहन अग्रवाल एमी में 3, सीजी में 15 साल रहें मंत्री

- **1997:** एबीवीपी का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्र नेता के रूप में राजनीति में प्रवेश।
- **1990:** मध्यप्रदेश विधानसभा के निर्वाचित सदस्य (उस समय के सबसे कम उम्र के विधायक) (वोट मार्जिन-2628), राज्य मंत्री स्थानीय प्रशासन, पर्यटन एवं संस्कृति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी स्वतंत्र प्रभार।
- **1997:** अविभाजित मध्य प्रदेश की विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में सम्मानित।
- **2013:** धान की अच्छी पैदावार के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार 2014: राज्य में अनाज के रिकॉर्ड उत्पादन के लिए केंद्र सरकार से कृषि कर्मण पुरस्कार।
- **2015:** फसलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु राष्ट्रीय कृषि कर्मण अवॉर्ड।
- **2016:** दालों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार।
- **2017:** राष्ट्रीय कृषि कर्मण पुरस्कार, कृषि नेतृत्व पुरस्कार।
- **2018:** खाद्यान्न उत्पादन हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार।
- **2018:** में विस चुनाव जीता।
- **2023:** में एक बार फिर चुनाव जीतकर मंत्री बने।

छत्तीसगढ़ के रायपुर से सांसद चुने गए बृजमोहन अग्रवाल ने साय कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया है। वह प्रदेश सरकार में शिक्षा मंत्री थे। बीते दिनों साय कैबिनेट की बैठक में बृजमोहन शामिल होने के लिए पहुंचे थे। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को अपना इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा देने के बाद बृजमोहन अग्रवाल भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि इतने साल मंत्री रहा। किसी को कोई कष्ट हुआ तो माफ कर दे। बृजमोहन अग्रवाल अब तक संसदीय कार्य मंत्री थे। उनके इस्तीफे के बाद चर्चा है कि मंत्री राम विचार नेताम को जिम्मेदारी दी जा सकती है। वहीं बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफे पर कांग्रेस ने तंज किया है। दो दिन पहले ही (17 जून को) विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया था। उन्होंने इस्तीफा विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह को सौंपा था। तब मीडिया से बृजमोहन ने कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व में सांसद का चुनाव लड़वाया है, तो सोच समझकर लड़ाया होगा। मुख्यमंत्री के अधिकारों में है कि वे 6 महीने तक मंत्री रख सकते हैं। सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, मैंने छत्तीसगढ़ विधानसभा की सदस्यता एक दिन पहले त्यागी थी और आज मैंने अपना मंत्री पद त्यागा है। मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने आज मेरा लोकसभा चुनाव जीतने पर स्वागत किया है। मैं सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। मेरे कार्यकाल में अगर किसी को कोई तकलीफ हुई है तो उनसे मैं क्षमा चाहता हूं। जनता और कार्यकर्ताओं का लगाव और प्रेम अब तक जैसा मुझे मिला है, उम्मीद करता हूं आगे भी वैसा ही मिलता रहेगा। मैं जनता की आवाज पहले छत्तीसगढ़ में था अब संसद में बनूंगा। रायपुर दक्षिण सीट की जनता की बात करते हुए भावुक हुए बृजमोहन ने कहा कि, जनता का मेरे ऊपर एहसान और ऋण है। किसी एक व्यक्ति को आठ बार और बिना गैप के लगातार विधायक बनाया। जब विधायक पद से विदाई की तो इतिहास बना कर की। लोकसभा में भेजा तो इतिहास बनाया। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं।

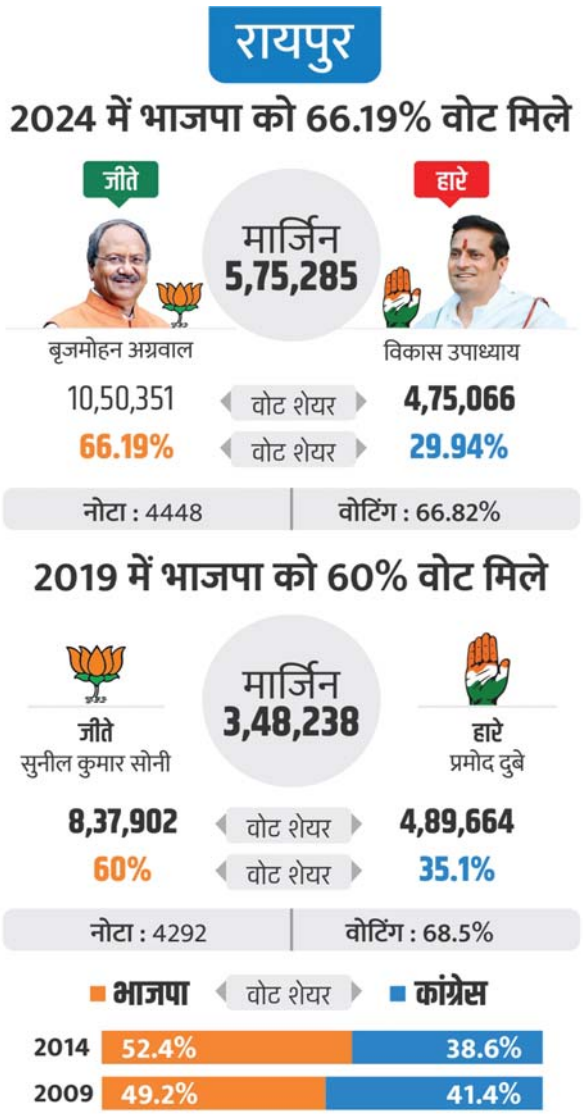

इस्तीफा से 24 घंटे पहले की बैठकें

इस्तीफा देने से 24 घंटे पहले ही बृजमोहन अग्रवाल ने अपने विभाग की समीक्षा की थी। उन्होंने प्रदेश के स्कूलों में स्मार्ट क्लास रूम बनाने और वित्त मंत्री से स्वीकृति के बाद 33 हजार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी।

रायपुर दक्षिण सीट खाली

इस्तीफा देने के बाद रायपुर दक्षिण सीट खाली हो गई है। चर्चा है कि प्रदेश में साल के अंत में नगरीय निकाय के साथ-साथ विधानसभा उप चुनाव भी हो सकते हैं। ऐसे में अभी से ही बड़ी संख्या में बीजेपी-कांग्रेस के नेता अपनी दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से ही रायपुर दक्षिण में बृजमोहन अग्रवाल का एकछत्र राज रहा है। उनके रहते यहां से किसी और को कभी भाजपा से टिकट मिला ही नहीं। पहली बार उनके सांसद बनने के कारण अब दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं।

छह महीने तक मंत्री बने रहने की थी चर्चा

बृजमोहन अग्रवाल के इस बयान के बाद ये चर्चा थी कि वो लगभग 6 महीने तक मंत्री बने रहेंगे। वो प्रदेश में 8 बार विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। 4 बार के मंत्री थे, मंत्री मंडल में सबसे ज्यादा अनुभवी नेताओं के रूप में बृजमोहन की गिनती होगी है।

18 साल मिनिस्टर रहे, 40 साल से विधायक अब सिर्फ सांसद कहलाएंगे

बृजमोहन क्यों नहीं बने केंद्रीय मंत्री

केंद्रीय मंत्री के लिए फिट क्यों बृजमोहन अग्रवाल

- 18 साल प्रदेश में मंत्री रहने का अनुभव
- भारतीय जनता पार्टी का पुराना अनुभवी चेहरा
- 8 बार विधायक का चुनाव जीतने का रिकॉर्ड
- लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी लीड से जीते
- राज्य सरकार में मंत्री पद का त्याग करेंगे इस वजह से दावेदारी दमदार रही
- लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय को 5.75 लाख वोट से हराया

यह रही अड़चन

- जातिगत समीकरणों की वजह से पीछे रह गए
- साहू समाज को साधने के चक्कर में भाजपा ने बृजमोहन के बजाय तोखन साहू को मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री का पद दे दिया

मोदी कैबिनेट विगत 9 जून रविवार की शाम शपथ ले चुकी है। सोमवार की सुबह का सूरज सवाल लेकर आया है। सियासी बातों में दिलचस्पी लेने वाले दो सवाल पूछ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ से तोखन साहू को मौका क्यों? और बृजमोहन अग्रवाल जैसे सीनियर नेताओं को साइड क्यों किया गया? बृजमोहन अविभाजित मध्यप्रदेश में 3 साल, छत्तीसगढ़ में 15 साल मंत्री रहे। 40 सालों से विधानसभा का चुनाव जीतते रहे, अब भी प्रदेश सरकार में मंत्री हैं मगर अब सिर्फ सांसद रह जाएंगे। बृजमोहन को लेकर उठ रहे सवालों के जवाब पढ़िए इस रिपोर्ट में। क्यों मंत्री नहीं बने बृजमोहन? इस सवाल के जवाब में भारतीय जनता पार्टी के सूत्र और राजनीति के जानकारों ने कुछ फैक्ट शेयर किए। पार्टी सूत्रों का कहना है कि इस बार संगठन में सिर्फ एक ही पैटर्न में काम हो रहा है, नए लोगों को मौका दो। अनुभवियों का बैलेंस बनाया जा रहा है। मगर शक्ति का बड़ा हिस्सा नए हाथों में है। जब साय मंत्रिमंडल बना तो इसका उदाहरण देखने को मिला।

राज्य बनने के बाद छत्तीसगढ़ से अब तक केंद्र में मंत्री

दिलीप सिंह जूदेव

- 29 जनवरी 2003-17 नवंबर 2003 तक वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री

रमेश बैस

- 13 अक्टूबर 1999-30 सितंबर 2000 तक केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्यमंत्री
- 30 सितंबर 2000-29 जनवरी 200 तक केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री
- 29 जनवरी 2003-8 जनवरी 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), खान मंत्रालय
- 9 जनवरी 2004-मई 2004 तक केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय

रमन सिंह

- 13 अक्टूबर 1999-29 जनवरी 2003 तक वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री

चरणदास महंत

- 12 जुलाई 2011-26 मई 2014 तक केंद्रीय राज्यमंत्री, कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

विष्णुदेव साय

- 26 मई 2014-30 मई 2019 तक केंद्रीय खान एवं इस्पात राज्यमंत्री
- 26 मई 2014-9 नवंबर 2014 तक केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्यमंत्री

रेणुका सिंह

- 30 मई 2019- 7 दिसंबर 2023 तक जनजातीय मामलों की राज्यमंत्री

दक्षिण का मार्ग कठिन

रायपुर दक्षिण की सीट से विधायक बनने वाले बृजमोहन जीत की गारंटी रहे हैं। मगर अब वो इस सीट को छोड़ देंगे। नियमों के मुताबिक सांसद बनने के बाद विधायकी छोड़नी पड़ती है। बृजमोहन जब हटेंगे तो उनकी जगह कौन चुनाव लड़ेगा, जो लड़ेगा वो बृजमोहन की तरह होगा या नहीं, उसे जनता स्वीकारेगी या नहीं, 5.75 लाख के अंतर से रायपुर लोकसभा जीतना बृजमोहन के चुनाव लड़ने की वजह से संभव हो पाया क्या वोटर इसी तरह भाजपा को इस सीट पर बिना बृजमोहन के स्वीकारेगा? ये तमाम समीकरण दक्षिण की जीती हुई सीट पर टेंशन बढ़ा रही है। क्योंकि बृजमोहन को वोटर्स ने इस सोच के साथ वोट किया था कि शायद उन्हें केंद्र में मंत्री पद मिले, जो हो न सका।

ये है बड़ी वजह

जानकार ये भी बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा और लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन समाजिक समीकरणों को समझकर किया है। मोदी कैबिनेट का हिस्सा बने तोखन साहू, साहू समाज से आते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाद लोकसभा चुनाव में इस समाज को साधने का काम किया है। यही वजह है कि तोखन को पद मिला और बाकी नेताओं को कुछ नहीं, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल भी हैं।

तो इसके क्या मायने हैं

तोखन साहू को राज्यमंत्री बनाना हैरान नहीं करता है, मगर अकेले उन्हें बनाना हैरान करता है। इससे साबित होता है मोदी की ताकत कमजोर नहीं हुई है। वो जो फैसला करते हैं वो पार्टी में होता है। पार्टी के भीतर मोदी जैसी फौलादी पकड़ रखते थे नतीजे आने के पहले रखते थे वह अब भी है।

छत्तीसगढ़ को एक ही राज्यमंत्री मिलता है

छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा सीटें हैं। यहां साल 2014 के लोकसभा चुनाव में 10 सांसद भाजपा के जीते। 2024 में भी भाजपा के 10 सांसद जीते। इसके बाद भी हमेशा से प्रदेश को केंद्र में प्रतिनिधित्व के रूप में सिर्फ एक राज्यमंत्री का पद मिलता है। किसी एक सांसद को राज्यमंत्री बना दिया जाता है। पूरा छत्तीसगढ़ भाजपा का हो चुका है। यहां 15 साल राज्य में भाजपा की सरकार रही, इस बार भी सरकार बनी, फिर लोकसभा में भी 10 सांसद इन्हीं के जीते, इसके बाद भी सिर्फ एक राज्यमंत्री पद देने की वजह से केंद्र द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य की अनदेखी की चर्चा गरमा गई है।

जब पूरी भाजपा हारी तब जीते थे बृजमोहन

2018 के विधानसभा चुनाव जब सामने आए पिछले 15 सालों सत्ता सुख भोग रही भाजपा सरकार को वोटर ने सिर्फ 15 सीट दी। जब भाजपा का हर बड़ा नेता चुनाव हार गया। जब रायपुर की सभी सीटों पर कांग्रेस के विधायक बने तो बृजमोहन अकेले थे जो दक्षिण की सीट जीतने में कामयाब रहे थे। सांसदों को लेकर ये देखा गया है कि उनका जनता से कनेक्शन उतना नहीं हो पाता जितना विधायक या मंत्रियों का होता है। बृजमोहन एक्टिव राजनीति के लिए जाने जाते रहे हैं। अब तक देखा गया है कि सांसद कुछ चुनिंदा बैठकों में दिखते हैं, संसद में भी सक्रियता छत्तीसगढ़ की अधिक दिखती नहीं। ऐसे में आगे बृजमोहन का होगा क्या, ये सवाल उनके समर्थकों को निराश कर रहा है।

मैं नरेन्द्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं...

लोकतंत्र के 2024 का महापर्व ऐसा 'लोकोत्सव' बना जिसने छह दशक के बाद नया इतिहास रचा है। इस अंतराल के बाद पहली बार केंद्र में कोई सरकार तीसरी बार सत्ता में वापस लौटी है। 4 जून को चुनाव परिणाम में इंद्रधनुषी गठबंधन के साथ वर्ष 1962 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे पहले व्यक्तित्व बन गए हैं जिन्होंने 9 जून को तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। 140 करोड़ नागरिकों की सेवा करने और देश को विकास की नई ऊंचाईयों पर ले जाने की प्रतिबद्धता को मिले जनादेश ने 'नए भारत' की आशा को विश्वास और आत्मविश्वास में बदला है। साथ ही, निरंतरता, स्थिरता और सुशासन की गारंटी के पर्याय प्रधानमंत्री के तीसरे कायर्काल में देश बड़े निणर्यों का एक नया अध्याय लिखेगा और 2047 के विकसित भारत का संकल्प होगा साकार...

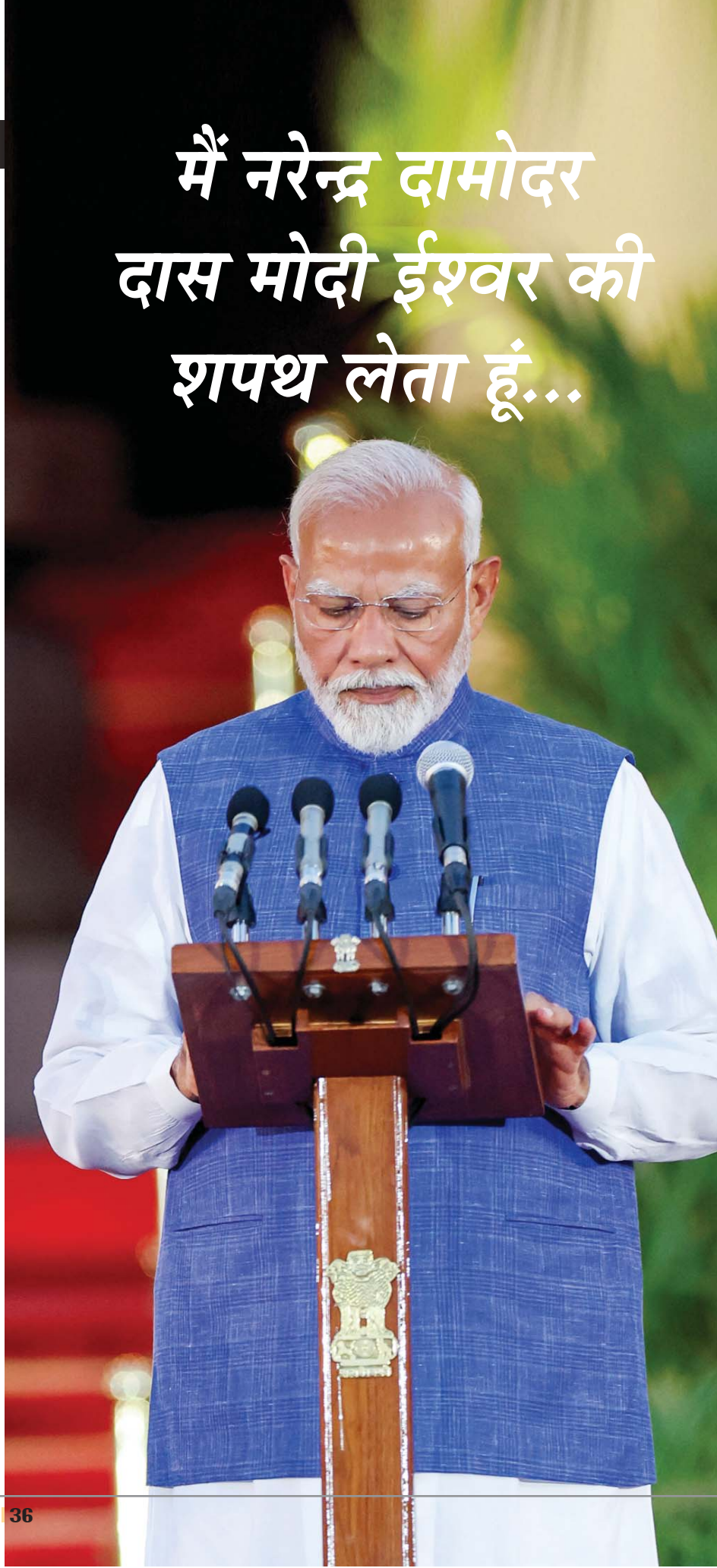

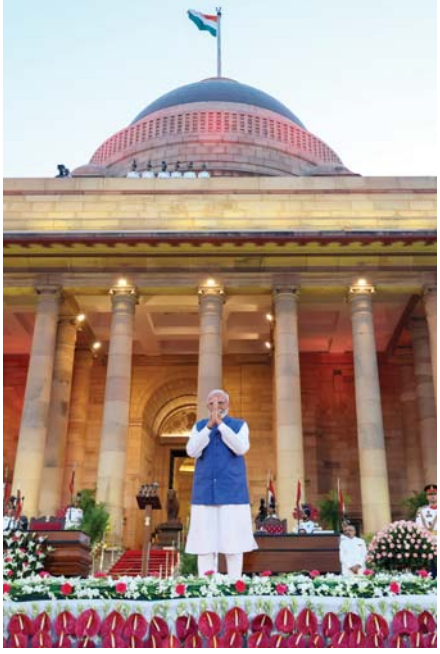

अक्सर इतने बड़े और ऐतिहासिक जनादेशों की व्याख्या के लिए राजनैतिक शब्दावली को कुदरती उपमाओं से शब्द उधार लेकर गढ़ना पड़ता है। आमतौर पर यह माना जाता है कि राजनीति में ऐसी अनहोनी एक-दो बार ही होती है। लेकिन जब लगातार तीसरी बार ऐसा होता है तो ऐसे जनादेश को दुर्लभ माना जाता है। ऐसा ही दुर्लभ नजारा 2024 के लोकतंत्र के महापर्व में देखने को मिला है।

चुनाव पूर्व कोई गठबंधन तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाकर विकसित भारत के संकल्प की शपथ ले चुका है। राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 9 जून की सायं 7.15 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली और उसके बाद 71 मंत्रियों ने शपथ ली। इसके साथ ही देश नया सूरज देख रहा है और शुरू हो चुकी है सुविचारित लक्ष्य के साथ अमृत काल में भारत को विकसित बनाने की स्वर्णिम यात्रा। अंत्योदय से राष्ट्रोदय के मंत्र के साथ देश को नई ऊंचाईयों पर ले जाने और निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रखने की सोच के साथ आगे बढ़ रही केंद्र सरकार ने समयबद्ध तरीके से योजनाओं की डिलिवरी सुनिश्चित कर 2014 से 2024 को सही अर्थों में विकास का दशक बना दिया है।

भारतीय लोकतंत्र के महापर्व-2024 की विजय दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जीत है। यह भारत के संविधान पर अटूट निष्ठा की जीत है। यह विकसित भारत के प्रण की जीत है। यह 'सबका साथ सबका विकास' के मंत्र की जीत है। यह 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। यह सभी की सक्रिय भागीदारी के साथ लोकतंत्र की विराट सफलता का प्रतीक है। हर नागरिक के लिए हमेशा से, देश सर्वोपरि रहा है। सेवाभाव से बड़ी राजनीति कोई नहीं हो सकती। इसलिए तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार सेवाभाव को सर्वोपरि रखने कि परंपरा को निरंतर मजबूत करने में जुट चुकी है। केंद्र सरकार जन आकांक्षाओं, जन-भावनाओं और जन-अपेक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। छह दशक के बाद, देश के मतदाताओं ने एक नया इतिहास रचा है। छह दशक बाद, किसी गठबंधन को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। जनता जनार्दन के साथ विश्वास का यह अटूट रिश्ता, यह लोकतंत्र की बहुत बड़ी शक्ति है। जनता का आशीर्वाद... नए उत्साह, नए उमंग के साथ काम करने की ऊर्जा का स्रोत बन चुका है।

चुनाव पूर्व गठबंधन हिंदुस्तान के राजनीतिक इतिहास में इतना सफल कभी भी नहीं हुआ है जितना की वर्ष 2024 के आम चुनाव में हुआ है। इस गठबंधन ने न केवल बहुमत हासिल किया है, बल्कि उसमें एक संदेश निहित है-स्थायित्व का, निरंतरता का। लोकतंत्र में सरकार चलाने के लिए बहुमत आवश्यक है, लेकिन देश चलाने के लिए सर्वमत बहुत जरूरी होता है। इस आम चुनाव में देशवासियों ने जो जनादेश दिया है उसका जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, मैं यहां से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार से हमें बहुमत देकर सरकार चलाने का सौभाग्य दिया है ये हम सबका दायित्व है कि हम सर्वमत का निरंतर प्रयास करेंगे और देश को आगे ले जाने के लिए हम कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेंगे।

पहले दिन से ही एक्शन में सरकार

शपथ लेने के अगले दिन ही 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी सहित मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने कार्यभार संभालते हुए आने वाले भविष्य की काम की गति का परिचय दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे पहले देश के अन्नदाताओं यानी किसान हित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर किए तो देर शाम हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में गरीबों को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ 3 करोड़ और नए पक्के मकान देने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। केंद्र सरकार का संदेश साफ है कि सुशासन, सेवा, गरीब कल्याण और किसानों को समर्पित सरकार सर्वांगीण, सर्वस्पर्शी और समावेशी विकास को प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कमर्चारियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शुरू से ही पीएमओ ने सेवा का अधिष्ठान और जनता का पीएमओ बनाने का प्रयास किया है।

केनवास के क्रॉस

विनोद साव

मुझे याद है प्रसिद्ध समालोचक प्रमोद वर्मा ने एक बार कहा था कि दुर्ग भिलाई की कवयित्रियों में एक विद्या गुप्ता तो हैं जो कविता लिख रही हैं. अब विद्या जी के रचनाकर्म में एक और रचनात्मक आयाम जुड़ गया है कि वे हिंदी के गद्य लेखन में भी सक्रिय हो गई हैं. यद्यपि गद्य लेखन वे पहले से करती आ रही हैं पर अब उनकी पहचान भी बन रही हैं. वे संस्मरण भी अच्छा लिखती हैं. कहानियां उनकी साहित्य की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में छप चुकी हैं... और अब उन्हीं कहानियों ने उनके संकलन में स्थान पा लिया है. 'मैं हस्ताक्षर हूँ' नाम से यह संकलन विगत दिनों साहित्य विमर्श प्रकाशन, गुरुग्राम, हरियाणा से छपकर आया है. अपने कथा संग्रह के नामानुकुल विद्या गुप्ता ने समकालीन कथा साहित्य में अपना हस्ताक्षर दर्ज कर दिया है. विद्या गुप्ता की कहानियों के बीच कला का एक दूसरा प्रतिरूप भी एक कहानी का आधार बनता है. यह चित्रकला पर है और इसलिए यह एक चित्रकार की कहानी है. यहां स्त्री–पीड़ा और संघर्ष चित्रकार की पत्नी के माध्यम से सामने आती है. कला का यह दूसरा प्रतिरूप दमनकारी भी सिद्ध हो सकता है. इस कहानी का शीर्षक भी अनोखा और स्पर्शीय है 'केनवास के क्रॉस'. यहां बस उसी एक कहानी की चर्चा होगी.

हर सृजनकर्मी के ऊपर एक 'क्रॉस' लटक रहा है. वह क्रॉस यानि सूली के नीचे बैठा अपनी कला में रंग भर रहा है या उनमें शब्दों को पिरो रहा है. वह कब क्रॉस पर लटक जाएगा, सूली पर चढ़ जाएगा उसे शायद पता भी न हो. उनके एक पुरोधा कलाकार ने कह भी दिया है कि 'अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे.' ये खतरे कलाकार के हिस्से में इसलिए आ जाते हैं कि उसे व्यवस्था विरोधी तो मान ही लिया गया है. यह व्यवस्था देश काल की भी हो सकती है या फिर उसकी अपनी निजी पारिवारिक स्व–निर्मित व्यवस्था भी हो सकती है जहाँ उसकी कला या सृजन पर आश्रित उसका परिवार है. पत्नी है और बच्चे भी हैं– "आकाश ... क्या देख रहे हो?क्या सोच रहे हो? कहाँ खोये हो?"

वह क्या देखता, क्या सोचता, क्यों सोचता?इसका जवाब उसके पास भी नहीं था. शायद इसका जवाब उसके भाल पर लिखी प्रारब्ध की इबारत में पहले से तय था.

कोई एक पल उछला और चित्र में ठहर गया...

जैसे कोई डाटा लोड कर कैनवास में खींचते हैं और कैनवास दागदार हो जाता है. दागी कैनवास से फिर किसी इमेज को वापस लाना मुश्किल होता है – बतवें. दोगला, आड़ा तिरछा, क्रॉस तो

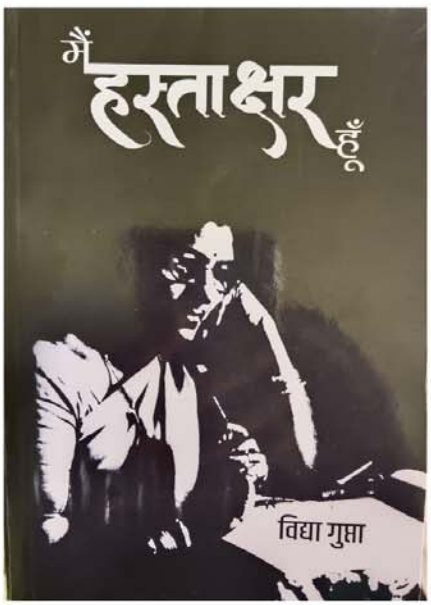

है पर सूली चढ़ने के समान है. इन्हें देखने में और कठिनाइयाँ हैं जिसे पार करना जरुरी है, संकट के इस वक्त में या क्रांति की अवधि में किसी व्यक्ति की आजादी के बारे में, जो उसे आमतौर पर मिली होती है, कुछ् हद तक दुबारा विचार करना जरुरी हो जाता है कि आखिर उसे अपने सृजनकर्म के लिए कितनी आजादी चाहिए घर परिवार, व्यवस्था और अपनी जिम्मेदारियों को सब कला की आग में झोक दे या इनसे अलग होकर, कटकर रहे. जिसमें वह किसी व्यवस्था की बलि न चढ़ जाए या उस पर आश्रित जन उसकी कलात्मक दुर्व्यवस्था की बलि न चढ़ जाए. या वह अपनी कला से प्राप्त कोई सुविधा भोगी जीवनशैली अख्तियार कर ले.

'आप आकाश के बारे में कुछ बोलना चाहेंगी?'

दीप्ति वैसी ही उलझी हुई–सी मंच पर खड़ी हो खोयी नजरों से कला वीथिका को नापते हुए... विशाल सभागार है, महान कला पारखी बैठे हैं जो आकाश की बुलंदियां नवाज रहे थे.

पत्नी दीप्ति की आवाज गूंजती है "हाँ, मैं स्वयं भी उन्हीं तस्वीर में से एक हूँ, जिसमें कोई रंग नहीं बचा... या भरा नहीं गया. खँडहर की तरह टूटा–फूटा एक संसार.. जिसकी दीवारों पर तीस वर्षों में एक भी ब्रश रंग का नहीं लगा.. सूखे फूलों से मुरझाए बच्चे.. जिनको सिर्फ समझौतों का कैनवास मिला... इस बासंती सूर्योदय के चित्र–सी एक भी सुबह जिसके जीवन में नहीं उतरी, न जीवन में दरिया पर बिखरी चांदनी के चित्र सी कोई रात... बेजुबान गौरय्या की आँखों की व्यथा पढ़ लेने वाला चित्रकार. . काश! एक बार तो पत्नी की आँखों को पढ़ पाता. जिसने अपनी सांसों से भी रिश्ता नहीं रखा, उसके सपनों और पारिवारिक जिम्मेदारियों की कौन कहे.

आज मैं ऐसे सच्चे कलाकार का हृदय से इस्तकबाल करती हूँ... मैं आकाश को अपनी अधूरी जिन्दगी की पीड़ा के भार से मुक्त करती हूँ और उनका सब कुछ आपकी संस्था को लौटाती हूँ, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ, कला का तौल कितना महंगा होता है. कला के सच्चे पुजारी का यथार्थ क्या होता है.. वह कैसे मर मर कर जीता है." ...और मरने के बाद अमर होता है.

संग्रह के ब्लर्ब में कथाकार गुलबीर सिंह भाटिया कहते हैं "विद्या गुप्ता की इन कहानियों में एक नयापन, एक ताजगी महसूस की जा सकती है. विषयों के चयन एवं उसके निर्वहन में उन्हें महारत हासिल है. अधिकतर कहानियां अनछुए पहलुओं पर लिखी गई कहानियां हैं. नारी मन की संवेदना एवं नारी जीवन में सहजता से प्रवेश कर आने वाली विडंबनाएं इन कहानियों का मुख्य स्वर हैं. ये कहानियां स्त्री जीवन के नए अध्याय खोल कर इस विमर्श को साहित्य में मजबूती के साथ स्थापित करती हैं.' संग्रह की लम्बी भूमिका समालोचक डॉ. सियाराम शर्मा ने लिखी है.

निवास : मुक्त नगर, जिला–दुर्ग (छ.ग.)
लेखक संपर्क : 09009884014

जरा हटके : अंक- 111

▸ वीरेन्द्र ओगले
कार्टूनिस्ट संपर्क : 09407980657

मोदी 3.0

नए मंत्रालय का आकार

केंद्र सरकार में 81 मंत्री हो सकते हैं; 72 बनाए जा चुके हैं

मोदी 1.0 2014-2019	मोदी 2.0 2019-24	मोदी 3.0 2024-
शुरू में	शुरू में	शुरू में
46 (24)	58 (25)	72 (31)
विस्तार के बाद	विस्तार के बाद	कैबिनेट मंत्रियों की संख्या ( ) में
76 (27)	78 (25)	

मोदी की कैबिनेट में महिलाएं

पहले मोदी मंत्रिमंडल में छह महिलाएं थीं. यह संख्या देश के इतिहास में सबसे ज्यादा है. उसके पहले यूपीए-1 सरकार में 2004-2009 तक सर्वाधिक तीन महिला कैबिनेट मंत्री थीं

मोदी 1.0 2014-2019	मोदी 2.0 2019-24	मोदी 3.0 2024-
शुरू में	शुरू में	शुरू में
10 (6)	6 (3)	11 (2)
विस्तार के बाद	विस्तार के बाद	कैबिनेट मंत्रियों की संख्या ( ) में
9 (6)	12 (2)	

सीनियर सिटिजंस क्लब

31 कैबिनेट मंत्रियों में 19 की उम्र 60 साल से ज्यादा

59 वर्ष औसत आयु है मोदी मंत्रिमंडल की

सबसे बुजुर्ग मंत्री

जीतनराम मांझी, 79 वर्ष
छोटे, लघु और मझोले उद्योग मंत्री
पार्टी: हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा (सेक्युलर)
राज्य: बिहार

...और सबसे युवा मंत्री

किंजारपू राममोहन नायडू, 36 वर्ष
नागरिक उड्डयन मंत्री
पार्टी: तेलुगु देशम पार्टी
राज्य: आंध्र प्रदेश

पूर्व मुख्यमंत्रियों की टीम

मोदी के अलावा अब छह पूर्व मुख्यमंत्री उनके मंत्रिमंडल में

नरेंद्र मोदी
पूर्व मुख्यमंत्री, गुजरात

राजनाथ सिंह
पूर्व मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

शिवराज सिंह चौहान
पूर्व मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश

मनोहरलाल खट्टर
पूर्व मुख्यमंत्री, हरियाणा

जीतनराम मांझी
पूर्व मुख्यमंत्री, बिहार

सर्वानंद सोनोवाल
पूर्व मुख्यमंत्री, असम

एच.डी. कुमारस्वामी
पूर्व मुख्यमंत्री, कर्नाटक

Anjali PRINTERS

The Quality Print Point

ALL TYPE DESIGN AND PRINTING JOBS...

THE BEST QUALITY PRINTING

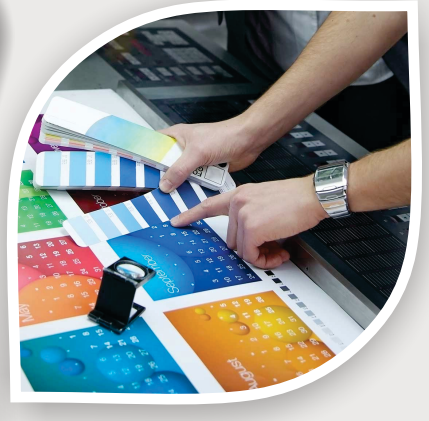

OFFSET PRINTERS

creative • printing • solutions

MAGAZINE, BROCHURE

- ★ Magazine
- ★ Brochur
- ★ Pamphlet
- ★ Calender
- ★ Enverlope
- ★ Book's
- ★ Visting Card
- ★ Letter Head
- ★ News Paper
- ★ Advertisement

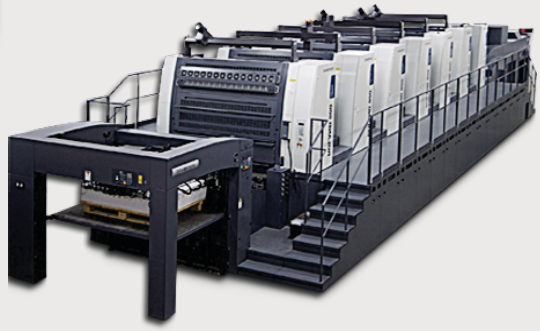

Office : Krishana Nagar, Santoshi Nagar, Raipur (C.G.)-492001

Mo. 78793-03247, **Email Id :** anjaliprinters.raipur@gmail.com

विष्णु के सुशासन से
संवर रहा छत्तीसगढ़

सुशासन और समग्र विकास के

6 माह

श्री नरेन्द्र मोदी
माननीय प्रधानमंत्री

श्री विष्णुदेव साय
माननीय मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

विकास की नई राह

- कृषक उन्नति से समृद्ध किसान, 3100 रुपए में ख़रीदा धान
- मिला दो वर्षों का 3716 करोड़ रुपए बकाया बोनस
- पीएम आवास से 18 लाख से अधिक परिवारों को अपना मकान, गरीबों का रखा ध्यान
- मुफ्त अनाज से गरीबों का कल्याण, एक करोड़ से अधिक परिवारों को 5 वर्षों तक राशन
- महतारी वंदन से महिलाओं को आर्थिक संबल, प्रतिवर्ष 12,000 रुपए की मदद से 70 लाख महिलाओं को मिला बल
- तेंदूपत्ता मानदेय अब बढ़कर प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए भुगतान, आदिवासी का सम्मान
- शासकीय भर्ती आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिली, युवाओं में चहुँओर खुशी
- भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित, युवा रहेगा अब निश्चिंत
- 'नियद नेल्लानार' से माओवादी समस्या का पूर्ण निदान, लड़ाई से आगे बढ़ विकास का विधान
- त्वरित निर्णय- सख्त प्रशासन, विगत 6 माह में, 129 माओवादी ढेर, 488 गिरफ्तार, 431 आत्मसमर्पण
- 'रामलला दर्शन योजना' से श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम की निःशुल्क यात्रा का मिल रहा सौभाग्य

सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास

Visit us : ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO ChhattisgarhCMO DPRChhattisgarh DPRChhattisgarh www.dprcg.gov.in छत्तीसगढ़ जनसंपर्क

छत्तीसगढ़ संवाद/आर.ओ. 12786/191